



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40]

नई दिल्ली, बुध्दिवार, मार्च 2, 2006/फाल्गुन 11, 1927

No. 40]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 2, 2006/PHALGUNA 11, 1927

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2006

सं. 4-1/2003-कारा.—बालकों के दत्तक ग्रहण से संबंधित मानदंडों, सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए, भारत सरकार ने दिनांक 29-5-1995 की अधिसूचना के तहत भारतीय बच्चों के दत्तक ग्रहण संबंधी संशोधित दिशा-निर्देश 1995 में जारी किए थे।

तत्पश्चात् घटित हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, दिशा-निर्देशों को आगे संशोधित किया गया है। भारत से दत्तक ग्रहण संबंधी दिशा-निर्देश-2006, जो पूर्ववर्ती दिशा-निर्देशों का स्थान लेंगे, आम जनता, स्वैच्छिक एजेंसियों और इस विषय से संबंधित अन्य की जानकारी एवं पालन के लिए हैं।

पी. नारायण मूर्ति, संयुक्त सचिव

भारत से दत्तक ग्रहण संबंधी दिशा-निर्देश — 2006

अध्याय - 1

प्रस्तावना

1.1 लक्ष्य और उद्देश्य:

इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य के०एल० पाण्डेय बनाम भारत संघ तथा अन्य के मामले में 1984 तथा 1991 के मध्य भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों में निर्धारित मानदंडों और सिद्धांतों और समय-समय पर न्यायालय के विभिन्न अंग निर्णयों के अंतर्गत देश से बाहर दत्तक ग्रहण को ठोस आधार प्रदान करना तथा बालकों का देश में दत्तक ग्रहण और सामान्यतः बाल कल्याण को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक सभी अन्य उपाय करना है।

1.2 इसका लक्ष्य यथासंभव अधिक से अधिक अनाथ बच्चों के लिए परिवार का पता लगाना तथा बाल अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन एवं देश से बाहर दत्तक ग्रहण संबंधी हेग कन्वेंशन (दोनों भारत द्वारा अनुसमर्थित) में यथा परिकल्पित उनके हितों की रक्षा करना है।

1.3 भारत सरकार ने अपने सांविधानिक अधिदेश के अनुसरण में बालकों के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार की है। इस नीति के महत्व का सारांश इस प्रकार है:

" बच्चे राष्ट्र की अत्यधिक महत्वपूर्ण सम्पत्ति हैं। उनका पालन-पोषण करना और ध्यान रखना हमारा दायित्व है। मानव विकास की हमारी राष्ट्रीय योजनाओं में बच्चों के कार्यक्रमों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए जिससे हमारे बच्चे बड़े होकर हृष्टपुष्ट नागरिक, शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से चुस्त तथा नैतिक रूप से स्वस्थ हों और वे समाज के लिए आवश्यक कौशलों तथा प्रेरणाओं से युक्त हों। सभी बालकों को उनके विकास की अवधि के दौरान उन्नति के सभी अवसर प्रदान करना हमारा उद्देश्य

होना चाहिए इससे सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने और असमानता को दूर करने का हमारा बड़ा प्रयोजन पूरा होगा।"

1.4 राष्ट्रीय बाल कल्याण नीति उस अत्यावश्यक भूमिका को भी महत्व देती है जिसे स्वैच्छिक संगठनों को बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन तथा समाज कल्याण सेवाओं के क्षेत्र में निभानी पड़ती है और इस नीति में घोषणा है कि राज्य का प्रयास ऐसे स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित और मजबूत करना होगा।

1.5 भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा देश से बाहर दत्तक ग्रहण में रखे गए भारतीय बच्चों के संरक्षण को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से 9 जनवरी, 2003 को देश से बाहर दत्तक ग्रहण संबंधी हेग कन्वेंशन 1993 पर हस्ताक्षर किए हैं और 6 जून, 2003 को उसका अनुसमर्थन किया है। हमारे देश में इस कन्वेंशन के कार्यान्वयन के उद्देश्य से, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय प्रशासनिक मंत्रालय के रूप में तथा केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) केन्द्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य कर रहे हैं।

1.6 बालकों के विकास के लिए पारिवारिक सहायता की आवश्यकता

समुदाय का और राज्य का दायित्व है कि अनाथ और निराश्रित बालकों को संस्थागत और गैर-संस्थागत दोनों प्रकार की सहायता प्रदान करें। भारत सरकार ऐसे बच्चों के पुनर्वास के लिए दत्तक ग्रहण को सर्वोत्तम गैर-संस्थागत सहायता के रूप में समझती है क्योंकि केवल पारिवारिक सहायता ही उन्हें अपनी क्षमता को प्राप्त करने का सबसे अच्छा अवसर प्रदान कर सकता है।

1.7 दत्तक ग्रहण प्रक्रिया की समीक्षा

भारत सरकार द्वारा 'भारतीय बच्चों के दत्तक ग्रहण संबंधी दिशा-निर्देश, 1995' 21 मई, 1995 को जारी किए गए थे। देश से बाहर दत्तक ग्रहण संबंधी हेग कन्वेंशन 1993 पर भारत द्वारा 6.6.2003 को अनुसमर्थन कर दिए जाने जैसे घटनाक्रमों को देखते हुए, इन दिशा-निर्देशों में अब और संशोधन करने का निर्णय लिया गया है।

इन दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देने से पहले, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसियों, दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसियों और दत्तक ग्रहण जांच एजेंसियों से सुझाव और विचार आमंत्रित किए गए।

"भारतीय बच्चों का देश से बाहर दत्तक ग्रहण संबंधी दिशानिर्देश, 2006"
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा
इस संबंध में जारी किए गए सभी पूर्ववर्ती दिशा-निर्देशों का अधिक्रमण करेंगे।

अध्याय - 2

प्राधिकरण और एजेंसियां

2.1 भारत सरकार

भारत सरकार में दत्तक ग्रहण से संबंधित सभी नीतिगत मामलों पर कार्रवाई सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा की जाती है। इस मंत्रालय के तत्वावधान में केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके बाद कारा कहा गया है), दत्तक ग्रहण संबंधी मामलों के लिए एक नोडल निकाय के रूप में कार्य करता है। यह सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन 18 मार्च, 1999 को पंजीकृत एक निकाय है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कारा के कृत्यों को संलग्नक - 1 पर सूचीबद्ध किया गया है।

2.2 केन्द्रीय प्राधिकरण:

सरकारी विभाग तथा उनकी सरकार द्वारा कोई अन्य विधिवत प्राधिकृत निकाय, जो देश से बाहर दत्तक ग्रहण संबंधी हेग कन्वेंशन, 1993 के अंतर्गत विदेशी देशों के केन्द्रीय प्राधिकरणों के रूप में अधिसूचित हैं, कारा द्वारा केन्द्रीय प्राधिकरणों के रूप में समझे जाएंगे।

2.3 कारा द्वारा सूचीबद्ध विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसियों को सूचीबद्ध विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसियां (ई.एफ.ई.ए.) कहा जाएगा:

कारा ऐसी सभी सूचीबद्ध विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसियों की एक सूची अनुमोदित/प्राधिकृत करेगी और रखेगी, जो अनिवासी भारतीयों (एन आर आई) सहित विदेशी प्रत्याशित दत्तक माता-पिता के आवेदनों को इसे अनुमोदन के लिए अग्रेषित कर सकती हैं।

2.4 देश से बाहर दत्तक ग्रहण के लिए मान्यता प्राप्त भारतीय एजेंसियां (आर आई पी ए)

कारा देश से बाहर दत्तक ग्रहण के लिए मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसियों (आर आई पी ए) को मान्यता देगी/प्रत्यायित करेगी । यह प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों में आर आई पी ए की सूची वर्ष में एक बार प्रकाशित करेगी । कारा इस सूची को जिला न्यायालयों में परित्यालित करने के लिए वर्ष में एक बार उच्च न्यायालयों को भेजेगी । आर आई पी ए 1993 के हेग कन्वेंशन के अनुसार मान्यता प्राप्त निकायों के रूप में कार्य करेंगे ।

2.5 दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसियां (ए सी ए)

उन राज्यों में और यहां तक कि बड़े नगर में जहां देश में दत्तक ग्रहण को प्रोत्साहित करने और देश से बाहर सभी दत्तक ग्रहणों की स्थिति में अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनेक मान्यता प्राप्त स्थापन और बाल कल्याण एजेंसियां हैं, एक केन्द्रीकृत एजेंसी अर्थात् दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी (ए सी ए) होगी । इसे पहले स्वैच्छिक समन्वय एजेंसी (वी सी ए) कहा जाता था ।

2.6 दत्तक ग्रहण जांच एजेंसियां (ए एस ए)

न्यायालय, जब चाहे, बालक का कल्याण सुनिश्चित करने की दृष्टि से दत्तक ग्रहण के आवेदनों की जांच करने हेतु, भारतीय बाल कल्याण परिषद या भारतीय समाज कल्याण परिषद या इसकी किसी शाखाओं/किसी स्वतंत्र, प्रतिष्ठित और शासकीय रूप से मान्यता प्राप्त बाल/समाज कल्याण एजेंसी से सहायता प्राप्त कर सकता है ।

2.7 भारतीय राजनयिक मिशन

विदेश में भारतीय राजनयिक मिशन उपेक्षा, दुर्व्यवहार, शोषण, दुरुपयोग के संबंध में विदेशी माता-पिता द्वारा गोद लिए गए भारतीय मूल के बालकों के रक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित केन्द्रीय/सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ सम्पर्क करेंगे । वे कारा से विदेशी नागरिकों (अनिवासी भारतीय/पी आई ओ सहित) द्वारा दत्तक ग्रहण के लिए मुक्त सभी भारतीय बालकों का विवरण वर्ष में एक बार प्राप्त करेंगे ।

भारतीय मिशनों को अपने अधिकार क्षेत्र में विदेशी सूचीबद्ध एजेंसियों तथा केन्द्रीय प्राधिकरणों के साथ परस्पर संवाद करने और गोद लिए गए बच्चों और उनके माता-पिता के सम्मेलन आयोजित करने की व्यवस्था करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ।

- 2.8 समय-समय पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुमोदन से कारा किसी मान्यता/नवीकरण प्रसंस्करण शुल्क लगा सकेगा ।

अध्याय - 3

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की भूमिका

- 3.1 बाल गृहों को लाइसेंस देना:

राज्य सरकारें ("राज्य सरकार" पर्याय में, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जहां कहीं लागू है, शामिल है) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में लागू संगत अधिनियम/कानून/नियमों के अधीन निराश्रित, परित्यक्त या अनाथ बालकों के दत्तक ग्रहण कार्यक्रमों में लगे सभी ऐसे बाल गृहों को लाइसेंस/मान्यता देंगी ।

- 3.2 राज्य सरकारें देश में दत्तक ग्रहण, 2004 से संबंधित दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार देश में दत्तक ग्रहण के लिए भारतीय दत्तक ग्रहण एजेंसियों को लाइसेंस/मान्यता देंगी और देश से बाहर दत्तक ग्रहण की मान्यता के लिए अनुरोध करने वाली भारतीय एजेंसियों के आवेदन-पत्रों को उचित सत्यापन के बाद केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी को अग्रेषित करेंगी । यदि राज्य सरकार ने देश में दत्तक ग्रहण कार्य करने के लिए संबंधित एजेंसी को अनुमति नहीं दी है, तो इस नई मान्यता के नवीकरण की सिफारिश नहीं करनी चाहिए । सभी एजेंसियों को राज्य के संगत अधिनियम के अधीन मान्यता के लिए योग्य होने के लिए लाइसेंसीकृत/पंजीकृत भी होना पड़ेगा ।

- 3.3 दत्तक ग्रहण एजेंसियों की सूची

उपर्युक्त बाल गृहों में से, राज्य सरकारें देश में दत्तक ग्रहण तथा देश से बाहर दत्तक ग्रहण का कार्य करने वाले ऐसे गृहों या एजेंसियों की अलग से एक सूची रखेगी तथा ऐसे सभी बच्चों की भी एक सूची रखेगी जो इन संस्थाओं में सक्षम प्राधिकरणों द्वारा दत्तक ग्रहण के लिए कानूनन मुक्त घोषित कर दिए गए हैं ।

3.4 राज्य सरकारों की भूमिका और कृत्य:

1. इसके क्षेत्राधिकार में सभी दत्तक ग्रहण एजेंसियों, देश से बाहर दत्तक ग्रहण के लिए मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसियों और दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसियों के दत्तक ग्रहण और कार्यक्रमों को मानीटर करना;
2. देश के भीतर परिवारों के साथ दत्तक ग्रहण या संरक्षकता में ऐसे बालकों के स्थापन को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना;
3. यदि किसी विशेष राज्य में कोई दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी नहीं हो तो दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी की स्थापना होने तक संबंधित राज्य सरकार का विभाग दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी के रूप में कार्य करेगा;
4. अनाथालय और अन्य पूर्ण आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) अधिनियम, 1960 और / या किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 लागू करें और/या बाल कल्याण संस्थाओं में बालक की देखरेख के लिए कुछ न्यूनतम मानकों को बनाए रखें। राज्य सरकारों द्वारा लाइसेंस/मान्यता नहीं दिए गए गृहों को दत्तक ग्रहण कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी;
5. देश से बाहर दत्तक ग्रहण के लिए नई मान्यता तथा मान्यता के नवीकरण हेतु दत्तक ग्रहण एजेंसियों से सभी आवेदन प्राप्त करें। समुचित सत्यापन के बाद यह अपनी स्पष्ट सिफारिश को निरीक्षण रिपोर्ट या अन्यथा सहायक दस्तावेजों के साथ कारा को भेजेगा;
6. दत्तक ग्रहण संबंधी सलाहकार समिति का गठन करें जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे:

(क)	सचिव, महिला एवं बाल कल्याण विभाग/समाज कल्याण/पंचायत राज	1	अध्यक्ष
(ख)	निदेशक, कल्याण/समाज कल्याण/महिला एवं बाल विकास	1	सदस्य
(ग)	दत्तक ग्रहण स्थापन एजेंसियों के दो प्रतिनिधि	2	सदस्य
(घ)	दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी का एक प्रतिनिधि	1	सदस्य
(ङ.)	दत्तक ग्रहण जांच एजेंसियों का एक प्रतिनिधि	1	सदस्य
(च)	समाज तथा बाल कल्याण के क्षेत्र में तीन विशेषज्ञ	3	सदस्य

समिति बाल कल्याणकारी उपायों, विशेष रूप से देश में बालकों के दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श करने और दत्तक ग्रहण से संबंधित नीतिगत मुद्दों के संबंध में सभी उपाय करने के लिए समय-समय पर बैठकें करेगी। इस समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

7. राज्य सरकार दत्तक ग्रहण कार्य के समन्वय, मानीटरिंग और विकास के लिए तथा दत्तक ग्रहण संबंधी सलाहकार समिति को सभी प्रकार की सहायता करने के लिए समाज कल्याण निदेशालय में एक दत्तक ग्रहण प्रकोष्ठ भी स्थापित करेगी। इस दत्तक ग्रहण प्रकोष्ठ में कम से कम एक अधिकारी और एक सहायक होना चाहिए या यदि अधिक स्टाफ चाहिए तो वह इसे राज्य में लाइसेंस/मान्यता प्राप्त एजेंसियों की संख्या पर आधारित होना चाहिए;
8. यह सुनिश्चित करें कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रावधानों, किशोर न्याय अधिनियम, 2000 पर आधारित राज्य किशोर न्याय नियमों तथा देश में दत्तक ग्रहण संबंधी दिशा-निर्देश, 2004 का पालन किया जाए;

9. राज्य सरकारें दत्तक ग्रहण एजेंसियों से बालकों के नए आगमन और मृत्यु के बारे में आंकड़े प्राप्त करेंगी और कारा को वार्षिक रूप से आंकड़े भेजेंगी; और
10. राज्य सरकारें राज्यों में कार्यरत सभी बाल कल्याण समितियों/किशोर न्याय बोर्डों को दत्तक ग्रहण मामलों से संबंधित आवधिक आंकड़े दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी और दत्तक ग्रहण प्रकोष्ठ को भेजने के निर्देश दे सकेंगी।

3.5 दत्तक ग्रहण एजेंसियों का निरीक्षण:

कारा/राज्य सरकार समय-समय पर तथा वर्ष में कम से कम एक बार सभी लाइसेंस और मान्यता प्राप्त स्थापन एजेंसियों का और बालकों की सेवा से जुड़े उनके कागजातों, दस्तावेजों और कार्यकलापों का निरीक्षण करेगी जिससे कि निम्नलिखित का सत्यापन किया जा सके कि :-

- (1) संगठन द्वारा बालक के हित में कल्याणकारी उपाय के तौर पर न कि वाणिज्यिक कार्यकलाप के तौर पर दत्तक ग्रहण का अनुसरण एक कार्यकलाप के रूप में किया जा रहा है;
- (2) गृह में दाखिल किए गए बालकों के उचित अभिलेखों का रख-रखाव किया जा रहा है।
- (3) दाखिल किए गए बालकों को संस्था या पोषण गृहों में उनकी देखरेख, शिक्षा और विकास के लिए गुणवत्ता वाली बाल देखरेख और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं;
- (4) किसी बालक को गोद लेने में या किसी बालक को संरक्षकता में रखने में रुचि रखने वाले व्यक्तियों की सूचियां संगठन द्वारा नियमित रूप से रखी जा रही हैं;
- (5) संगठन के लेखाओं का रख-रखाव किया जा रहा है और उनकी लेखा परीक्षा बिना किसी विलम्ब के वार्षिक रूप से की जा रही है तथा यह कि लेखा

परीक्षकों की रिपोर्टें इसकी पुष्टि करती हैं कि वे खाते सही और सत्य हैं; कोई भी संगठन, जो विदेश से धनराशि प्राप्त करता है गृह मंत्रालय के पास विधिवत पंजीकृत है और अन्यथा इसने विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के उपबंधों का पालन किया है;

- (6) संगठन गोद दिए गए बालकों के कल्याण के बारे में प्रगति रिपोर्टें नियमित रूप से प्राप्त कर रहा है;
- (7) सामाजिक कार्य का अनुभव प्राप्त योग्य स्टाफ बालकों की देखरेख का पर्यवेक्षण करने के लिए एजेंसी/संगठन द्वारा नियोजित किया गया है या ऐसे स्टाफ के लिए उनकी पहुंच है;
- (8) प्रत्याशित दत्तक माता-पिता के साथ दत्तक ग्रहणपूर्व देखरेख/पोषण देखरेख में रखे गए बालकों की स्थिति में, मामलों को वैध बनाया गया है;
- (9) सभी मामलों में दत्तकपूर्व पोषण देखरेख में दिए गए बालकों के लिए अलग रजिस्टर रखा गया है; और
- (10) भावी दत्तक माता-पिता का केन्द्रीय रजिस्टर रखा गया है ।

3.6 कार्य-निष्पादन की मानीटरिंग

इन एजेंसियों की कार्य प्रणाली को मानीटर करने के लिए राज्य सरकार दत्तक ग्रहण कार्य में लगी सभी दत्तक ग्रहण मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसियों (आर आई पी ए) तथा लाइसेंस प्राप्त दत्तक ग्रहण स्थापन एजेंसियों (एल ए पी ए) से प्रत्येक तिमाही में सूचना और आंकड़े मंगाएगी । इन आंकड़ों को केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाने वाले प्रपत्र में मंगाया जाएगा । सभी दत्तक ग्रहण एजेंसियों से वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षित लेखा विवरण प्राप्त किए जाएंगे ।

- 3.7 राज्य सरकार, देश से बाहर बालकों का दत्तक ग्रहण करने की अपेक्षा उनका देश में दत्तक ग्रहण किए जाने को सक्रियतापूर्वक प्रोत्साहित करने पर तरजीह देने के लिए, जरूरी समझे जाने वाले सभी उपाय करेगी । दत्तक

ग्रहण द्वारा स्थापन के जरिए संस्थाओं में बालकों के पुनर्वास के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा/विशेष प्रयास किए जाएंगे ।

- 3.8 राज्य सरकार गैर-कानूनी दत्तक ग्रहण कार्य में संलिप्त व्यक्तियों और संस्थाओं तथा नर्सिंग होमों एवं अस्पतालों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करेगी ।
- 3.9 दत्तक ग्रहण के लिए मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसियों (आर आई पी ए) की मान्यता रद्द करना/समाप्ति

किसी मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी द्वारा दिशा-निर्देशों के उल्लंघन की सूचना की स्थिति में, राज्य सरकार उचित कार्रवाई करने के लिए कारा को सूचित करेगी । कारा द्वारा मान्यता रद्द करने/वापस लेने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा अन्य मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसियों के माध्यम से दत्तक ग्रहण के प्रतीक्षारत बालकों के लिए उपयुक्त पुनर्वास योजनाएं सुनिश्चित करनी पड़ेंगी ।

* * * *

अध्याय-4

देश से बाहर दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया

भारत के उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि किसी बालक को गोद लेने के इच्छुक विदेशी/अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति (जो लागू हो) से प्राप्त आवेदन सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या लाइसेंस प्राप्त समाज या बाल कल्याण एजेंसी द्वारा या ऐसे मामलों को प्रायोजित करने के लिए उस विदेशी सरकार के विभाग द्वारा प्रायोजित किया जाए जिसका वह विदेशी निवासी है । विदेशी एजेंसी को कारा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक " प्राधिकृत " एजेंसी भी होना चाहिए । भारत में किसी भी समाज या बाल कल्याण एजेंसी को किसी विदेशी/अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति द्वारा किसी बालक को गोद लेने के किसी आवेदन पर सीधे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए ।

- 4.1 **विदेशी प्रत्याशित दत्तक माता या पिता/माता-पिता (एफ पी ए पी) के लिए मानदंड:**

- 5 वर्षों से स्थायी संबंधों वाले विवाहित दम्पति की आयु, वित्तीय व स्वास्थ्य दशा और बालक का पालन-पोषण करने के लिए समुचित आय का उल्लेख गृह अध्ययन रिपोर्ट में स्पष्टतः किया जाना चाहिए ।

- 90 वर्ष या उससे कम की संयुक्त आयु वाले प्रत्याशित दत्तक माता-पिता शिशुओं और छोटे बालकों को गोद ले सकते हैं। इन प्रावधानों को बड़े बालकों और विशेष जरूरत वाले बच्चों जैसे अपवादात्मक मामलों में गृह अध्ययन रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताए गए कारणों से उचित रूप से छूट दी जा सकती है। तथापि, किसी भी दशा में प्रत्याशित दत्तक माता-पिता में किसी की भी आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 45 वर्ष की आयु वाले एकल व्यक्ति (अविवाहित, विधुर/विधवा, तलाकशुदा) भी गोद ले सकते हैं।
- एकल दत्तक माता/पिता और बालक की आयु का अंतर 21 वर्ष या इससे अधिक होना चाहिए।
- विदेशी प्रत्याशित दत्तक माता-पिता को किसी भी स्थिति में 30 वर्ष से कम तथा 55 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
- भारत से दूसरे बच्चे के दत्तक ग्रहण के बारे में तभी विचार किया जाएगा जब पहले बालक का कानूनन दत्तक ग्रहण पूर्ण हो जाए।
- समलैंगिक दम्पति गोद लेने के पात्र नहीं हैं।

देश से बाहर दत्तक ग्रहण के सभी मामलों में निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा:

उपाय-1 सूचीबद्ध विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी (ई एफ ए ए)

- आवेदक को सूचीबद्ध विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी/केन्द्रीय प्राधिकरण/अपने देश के सरकारी विभाग, जिसके वे निवासी हैं, के पास सम्पर्क या पंजीकृत करना पड़ेगा जो गृह अध्ययन रिपोर्ट (एच आर एस) आदि तैयार करेंगे। "गृह अध्ययन रिपोर्ट" की वैधता दो वर्षों की अवधि के लिए होगी। दो वर्ष पहले तैयार की गई गृह अध्ययन रिपोर्ट को रेफरल पर अद्यतन किया जाएगा।
- आवेदक को भारत से किसी बालक को गोद लेने के लिए सक्षम प्राधिकरण से अनुमति लेनी चाहिए। जहां ऐसे केन्द्रीय प्राधिकरण या सरकारी विभाग न हों तो वहां सूचीबद्ध एजेंसी द्वारा दस्तावेजी प्रमाण सहित अपेक्षित कागजातों के साथ आवेदनों को भेजा जा सकता है कि उस आवेदक को भारत से गोद लेने की अनुमति दी गई है।

- दत्तक ग्रहण आवेदन डोजियर में संलग्नक-2 में निर्धारित सभी दस्तावेज होने चाहिए। सभी दस्तावेजों को नोटाराइज किया जाना है। नोटरी के हस्ताक्षर या तो भारतीय दूतावास/उच्चायोग या प्राप्त करने वाले देश के उचित सरकारी विभाग द्वारा सत्यापित किए जाने हैं। यदि अंग्रेजी से अन्य किसी और भाषा में हो तो सत्यापित दस्तावेज का अनुवाद उसके साथ अवश्य हो।
- संबंधित दत्तक माता-पिता के आवेदन की एक प्रति गृह अध्ययन रिपोर्ट की प्रतियों के साथ मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी को सूचीबद्ध विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी (ई.एफ.ए.ए.) या उस देश के केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा अग्रेषित की जानी चाहिए।

उपाय-2 मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी (आर आई पी ए)

- दस्तावेजों के प्राप्त होने पर, भारतीय एजेंसी आवेदक के साथ देश से बाहर दत्तक ग्रहण के लिए कानूनी रूप से मुक्त बालक के विषय में यह प्रयास करेगी कि वह बालक आवेदक के साथ प्रायः हर दृष्टि से उपयुक्त रहेगा।
- यदि 3 माह के भीतर कोई उपयुक्त मैच नहीं हो पाता है तो मान्यता प्राप्त स्थापन एजेंसी सूचीबद्ध विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी (ई एफ ए) और कारा को सूचित करेगी।

उपाय-3 बालक का देश से बाहर दत्तक ग्रहण के लिए मुक्त हो जाने पर - दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी द्वारा अनुमति

- मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी द्वारा किसी बालक को देश से बाहर दत्तक ग्रहण में रखे जाने का प्रस्ताव किए जाने से पहले, इसे दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी के पास भारतीय स्थापन के लिए सहायता हेतु आवेदन करना चाहिए।
- बालक दत्तक ग्रहण के लिए कानूनी रूप से मुक्त होना चाहिए। दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी 30 दिन के भीतर उपयुक्त प्रत्याशित भारतीय दत्तक माता/पिता का पता लगाएगी, ऐसा न होने पर देश से बाहर दत्तक ग्रहण के लिए अनुमति प्रमाणपत्र जारी करेगी।
- दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी इस संबंध में जारी किए गए अतिरिक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार 6 वर्ष से अधिक की आयु के बालकों, सहोदर भाई या बहन या जुड़वां बच्चों तथा विशेष देखभाल की

जरूरतों वाले बालकों की स्थिति में देश से बाहर दत्तक ग्रहण के लिए 10 दिन के भीतर अनुमति-पत्र जारी करेगी ।

- यदि दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी 30 दिनों के भीतर उपयुक्त भारतीय माता या पिता/माता-पिता नहीं ढूँढ सकती है तो दत्तक ग्रहण एजेंसी के लिए 31वें दिन अनुमति प्रमाणपत्र जारी कर देगी ।
- यदि दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी की स्वीकृति 31वें दिन नहीं दी जाती है, तो दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी की स्वीकृति मान ली जाएगी बशर्ते कि 30 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी ने स्पष्टीकरण नहीं मांगा हो ।
- अनिवासी भारतीय माता/पिता (माता-पिता) (माता या पिता) जिनके पास भारतीय पासपोर्ट हो, उन्हें दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी की स्वीकृति से छूट दी जाएगी परन्तु उन्हें दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी अन्य प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ेगा ।

उपाय-4 मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी द्वारा विदेशी प्रत्याशित दत्तक माता-पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट के साथ बाल अध्ययन रिपोर्ट का मिलान करना:

- सफलतापूर्वक मिलान करने के बाद, मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी कारा को "अनापत्ति प्रमाणपत्र" जारी करने के लिए संलग्नक - 3 के अनुसार पूरा डोजियर अग्रेषित करेगी ।

उपाय-5 कारा द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र (एन ओ सी) जारी करना

- मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी विदेशी/भारतीय मूल के माता-पिता की स्थिति में कारा के अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए आवेदन, दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी का अनुमति प्रमाणपत्र प्राप्त हो जाने के बाद ही, करेगी ।
- कारा सभी प्रकार से पूर्ण दत्तक ग्रहण डोजियर प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के अंदर "अनापत्ति प्रमाणपत्र" जारी करेगी ।
- यदि कारा द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाए या स्पष्टीकरण मांगा जाए, तो इसका उत्तर मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी द्वारा 10 दिन के भीतर दिया जाएगा ।
- कोई भी भारतीय स्थापन एजेंसी कारा से "अनापत्ति प्रमाणपत्र" लिए बिना, देश से बाहर दत्तक ग्रहण के लिए सक्षम न्यायालय में आवेदन दायर नहीं कर सकती है ।

उपाय-6 न्यायालय में याचिका दायर करना:

- कारा से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त हो जाने पर, मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी सक्षम न्यायालय में 15 दिनों के अंदर दत्तक ग्रहण/संरक्षकता के लिए याचिका दायर करेगी ।
- सक्षम न्यायालय विदेशी प्रत्याशित दत्तक माता-पिता के साथ बालक के स्थापन के लिए उचित आदेश जारी कर सकता है ।
- माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार, संबंधित न्यायालय 2 माह के भीतर मामले को निपटा सकता है ।

उपाय-7 पासपोर्ट और वीजा:

- मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी को बालक के पक्ष में भारतीय पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में आवेदन करना पड़ता है ।
- संबंधित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय 10 दिन के अंदर पासपोर्ट जारी करेगा ।
- तत्पश्चात्, संबंधित देश के कांसुलेट/दूतावास/उच्चायोग द्वारा बालक के लिए वीजा प्रवेश परमिट जारी किया जा सकता है ।

उपाय-8 दत्तक देश को बालक का जाना:

- दत्तक माता या पिता/माता-पिता को भारत में आना पड़ेगा और बालक को लेकर अपने देश वापस जाना होगा

4.2 पात्र बालकों के लिए मानदंड:

- बालक, दत्तक ग्रहण के लिए कानूनी रूप से मुक्त होना चाहिए ।
- दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी/राज्य सरकार से स्वीकृति सभी बालकों के लिए आवश्यक है, लेकिन इसमें वे बालक शामिल नहीं हैं जिनके बारे में दिशा-निर्देशों के अनुसार छूट दे दी गई है ।

- सहोदर भाई या बहनों/जुड़वां बच्चों/तीन जुड़वां बच्चों को, असाधारण मामलों को छोड़कर, अलग नहीं किया जा सकता ।
- दो असम्बद्ध बालकों का प्रस्ताव एक समय में किसी विदेशी परिवार के लिए नहीं किया जा सकता ।
- जहां तक संभव हो सके, बालक को 12 वर्ष का हो जाने से पहले ही उसे दत्तक ग्रहण में रखा जाए ।
- जहां कहीं लागू हो, बालक की सहमति प्राप्त करनी होगी ।

4.3 जहां कोई सूचीबद्ध विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी (ई.एफ.ए.ए.) नहीं हो:

यदि कोई भारतीय नागरिक ऐसे देश में निवास कर रहा है, जहां दत्तक ग्रहण के संबंध में कोई सूचीबद्ध एजेंसी नहीं है, वहां कारा किसी संगठन या भारतीय दूतावास द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्ति को इन दिशा-निर्देशों में तथा अन्य दस्तावेजों में यथा निर्धारित गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने, वचनबंध देने की अनुमति दे सकेगी । उक्त आवेदन भारतीय दूतावास के अनुमोदन से कारा को अग्रेषित किया जाए ।

यदि किसी देश में कारा द्वारा सूचीबद्ध कोई विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी नहीं है, तो उस देश का संबंधित सरकारी विभाग/मंत्रालय या किसी प्राधिकृत निकाय कारा को प्रत्याशित दत्तक माता-पिता की मूल आवेदन और संबंधित दस्तावेज भारतीय दूतावास/उच्चायोग के माध्यम से भेज सकता है । निवासी गैर-नागरिकों की स्थिति में जहां मेजबान सरकार मामलों को प्रायोजित करने की इच्छुक न हो, प्रलेखन कार्य उस देश के दूतावास के माध्यम से किया जा सकता है, जिस देश का आवेदक है । तथापि, सभी मामलों में गृह अध्ययन रिपोर्टें अर्हता प्राप्त एजेंसी/सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा तैयार करनी होंगी । यदि कारा कागजात प्राप्त कर लेती है, तो वह उन कागजातों को केवल इसके द्वारा अनुमोदित किए गए गृह अध्ययन रिपोर्ट के बाद ही आगे कार्रवाई करने के लिए किसी मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी (आर.आई.पी.ए.) के पास भेजेगी । उसके बाद अपनाई जाने वाली पद्धति वही होगी जिसका उल्लेख प्रक्रिया में किया गया है ।

4.4 भारत में रह रहे विदेशी नागरिक:

भारत में एक वर्ष या उससे अधिक समय से निवास कर रहे, विदेशियों के मामले में गृह अध्ययन रिपोर्ट तथा अन्य संबंधित कागजात मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी द्वारा तैयार किए जाएं, जो बालक की संरक्षकता के लिए ऐसे विदेशियों के आवेदन पर कार्रवाई करती है। संबंधित दूतावास/हाई कमीशन द्वारा इस आशय का वचनबंध दिया जाना चाहिए कि बालक को उस देश में कानूनी रूप से गोद लिया जाएगा और उस एजेंसी/संगठन का उल्लेख भी किया जाना चाहिए जो प्रगति रिपोर्ट भेजेगी और जब कभी बालक को विदेश ले जाया जाए तो किसी विघटन की स्थिति में बालक का ध्यान रखेगी। लेकिन विदेशी प्रत्याशित दत्तक माता-पिता (एफ पी ए पी) के स्थाई निवास के देश में सक्षम प्राधिकरण से एक प्रमाणपत्र अपेक्षित है जिसमें यह उल्लेख हो कि बालक को देश में प्रवेश करने और यथा समय गोद लिए जाने की अनुमति दी जाएगी।

4.5 विदेश ले जाए गए बालक के अधिकार:

जब न्यायालय दत्तक माता-पिता को बालक के संरक्षकों के रूप में नियुक्त करने के आदेश देता है तो उस आदेश में दत्तक माता-पिता का एक वचनबंध भी होगा कि वे बालक की रक्षा और उसके हितों का भरसक संरक्षण करेंगे और यह कि बालक को प्राप्तकर्ता राज्य में आदेश की तारीख से अधिक से अधिक दो साल में कानूनन गोद ले लिया जाएगा। प्राप्तकर्ता राज्य में इस प्रकार के दत्तक ग्रहण पर देश के कानूनों के अंतर्गत बालक को अंतर्राष्ट्रीय कानून में मान्य सभी अधिकार होंगे।

* * * *

अध्याय - 5

मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसियां (आर आई पी ए)

- 5.1 केवल ऐसी स्वैच्छिक एजेंसियां/संस्थाएं, जो बालकों की उन्नति और विकास के लिए मुख्य रूप से बाल कल्याण कार्यक्रमों में लगी हुई हैं, वे अपने समस्त कार्यकलापों के एक भाग के रूप में दत्तक ग्रहण संबंधी मामलों में कार्रवाई कर सकती हैं और राज्य सरकार के माध्यम से कारा को देश से बाहर दत्तक ग्रहण करने के लिए मान्यता हेतु आवेदन कर सकती हैं। केवल मान्यता प्राप्त एजेंसियां देश से बाहर दत्तक ग्रहण कार्य कर सकती हैं। मान्यता प्राप्त

भारतीय स्थापन एजेंसियों को देश से बाहर दत्तक ग्रहण संबंधी आवेदनों पर कार्रवाई करने के प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त निकाय के रूप में जाना जाएगा ।

5.2 प्राधिकरणों के साथ सूचीकरण:

बालकों की देखरेख और अभिरक्षा में या अनाथ, परित्यक्त, निराश्रित, उपेक्षित या त्यागे गए बालकों के दत्तक ग्रहण कार्य में या संबंधित किसी अन्य कार्यकलाप में लगी हुई प्रत्येक संस्था और बाल कल्याण एजेंसी को संबंधित राज्य सरकार द्वारा तत्काल सूचीबद्ध किया जाएगा और ऐसी सूची कारा को भेजी जाएगी ।

5.3 भारतीय स्थापन एजेंसी की मान्यता के लिए मानदंड:

किसी भी एजेंसी को देश से बाहर दत्तक ग्रहण के स्थापन कार्य में तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि वह राज्य सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त नहीं कर लेती और कारा द्वारा मान्यता प्राप्त न हो । देश से बाहर दत्तक ग्रहण कार्य करने की इच्छुक कोई भारतीय एजेंसी संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को मान्यता के लिए आवेदन करेगी और केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्रदान की गई केवल इस प्रकार की एजेंसियां ही देश से बाहर दत्तक ग्रहण कार्य पर कार्रवाई करने के लिए पात्र होंगी । ऐसी एजेंसियों का नाम " मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसियां " होगा । मान्यता प्रदान करने के लिए सामान्य मानदंड इस प्रकार होने चाहिए:

(क) यह, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन एक पंजीकृत सोसाइटी या पूर्त न्यास अधिनियम के अधीन सृजित एक न्यास, या किसी उपयुक्त विधि के अधीन पंजीकृत एक संगठन हो और इसने गत पांच वर्षों के दौरान महिला एवं बाल कल्याण के लिए कार्य किया हो;

(ख) मुख्य रूप से बाल कल्याण कार्यक्रमों में कार्य कर रही केवल ऐसी स्वैच्छिक एजेंसियां जो अपने सकल कार्यकलापों के एक अंग के रूप में दत्तक ग्रहण कार्य करती हों, केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को देश से बाहर दत्तक ग्रहण के लिए मान्यता हेतु आवेदन कर सकती हैं;

- (ग) संगठन को अनाथालय और अन्य पूर्त आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) अधिनियम, 1960 और/या किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 और/या किसी वैकल्पिक नियमों या आदेश के अधीन बाल कल्याण संस्थाओं में बाल देखरेख के लिए कतिपय न्यूनतम मानक बनाए रखने हेतु राज्य सरकार द्वारा विधिवत लाइसेंस प्राप्त/मान्यता प्राप्त होना चाहिए। संगठन को देश से बाहर मान्यता के लिए आवेदन करते समय, दत्तक ग्रहण के क्षेत्र में तीन वर्ष से कार्य कर रहा हो। योग्य मामलों में, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा जम्मू-कश्मीर में कार्यरत संगठनों के लिए इसमें छूट होगी;
- (घ) संगठन के पास, किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 41(4) तथा राज्यों के तदनु रूप किशोर न्याय नियमों के अनुसार, देश में दत्तक ग्रहण कार्य करने के लिए संबंधित राज्य सरकार से मान्यता का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए;
- (ङ.) जब दत्तक ग्रहण कार्यक्रम किसी बड़े संगठन का भाग हो, दत्तक ग्रहण कार्यक्रम संचालित करने और उसे निकट से मानीटर करने के लिए एक उप-समिति होनी चाहिए। इस समिति में बाल विकास/समाज कल्याण/विधि के क्षेत्र में अनुभव वाले कम से कम कुछ व्यावसायिक सदस्य होंगे;
- (च) इसमें शिशुओं सहित बालकों के संरक्षण और देखरेख के लिए उपयुक्त आवासीय संस्था/गृह होना चाहिए;
- (छ) इसे गैर-वाणिज्यिक और लाभ रहित आधार पर संचालित किया जाना चाहिए;
- (ज) इस संगठन के मुख्य कार्यपालक को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों, भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों और मान्यता एवं नवीकरण के समय कारा द्वारा लगाई गई शर्तों, यदि कोई हो, का पालन करने के लिए एक लिखित वचनबंध पर हस्ताक्षर करने का इच्छुक होना चाहिए;
- (झ) संबंधित राज्य सरकार द्वारा एजेंसी की मान्यता की सिफारिश की जानी चाहिए; और

(ज) इसके पास दत्तक ग्रहण एजेंसी के संचालन के लिए अपेक्षित व्यावसायिक स्टाफ होना चाहिए ।

किसी भारतीय एजेंसी को मान्यता इन दिशा-निर्देशों में निर्धारित शर्तों के अधीन, सामान्य तौर पर 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी । इस संबंध में कारा का निर्णय अंतिम होगा ।

5.4 प्रत्याशित दत्तक माता-पिता की सूची:

प्रत्येक मान्यता प्राप्त/लाइसेंस प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी सभी पंजीकृत भावी भारतीय दत्तक माता-पिता की एक सूची नियमित रूप से रखेगी जिसमें उनके नाम, पते तथा अन्य संगत आंकड़े होंगे । भारतीय पासपोर्टों वाले अनिवासी भारतीयों को इन एजेंसियों के पास पंजीकृत किया जा सकता है ।

5.5 मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी द्वारा अनुसरण किए जाने वाले उपाय: उपाय-1 बालकों का दाखिला

- किसी मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी में अभ्यर्पित बालकों सहित दाखिल किए गए बालकों के नाम कारा द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सभी उपलब्ध जानकारियों के साथ दाखिला रजिस्टर में दर्ज किए जाने चाहिए । सभी बालकों और नए आए हुए बालकों की सूची राज्य सरकार के दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी/दत्तक ग्रहण प्रकोष्ठ को मासिक आधार पर भेजी जानी चाहिए । एजेंसी में किसी बालक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में, उसकी सूचना तत्काल राज्य सरकार/संबंधित प्राधिकरण को देनी होगी ।
- प्रत्येक मान्यता प्राप्त/लाइसेंस प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी प्रत्येक बालक के लिए एक अलग फाइल रखेगी, जिसमें बालक का पूर्ण इतिवृत्त होगा । इसके अतिरिक्त, अभ्यर्पण, जैविक माता द्वारा छोड़े गए बालक का सामान तथा बालक से संबंधित अन्य अपेक्षित जानकारी का विशेष ब्यौरा रखा जाएगा/ निर्धारित/प्रलेखित किया जाएगा । गैर-मान्यता प्राप्त एजेंसियों सहित अन्य एजेंसियों से संबंधित बालकों के मामलों में किसी एजेंसी को कार्रवाई करने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि संबंधित बालक को न्यूनतम एक माह की अवधि के लिए इसकी अभिरक्षा में कानूनी रूप से तथा शारीरिक रूप से हस्तांतरित नहीं कर दिया गया हो ।
- एजेंसी में किसी बालक को प्रवेश दिए जाने पर, उस एजेंसी को 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति/स्थानीय प्राधिकरण को सूचित करना पड़ेगा ।

उपाय-2 दत्तक ग्रहण के लिए बालक का कानूनी रूप से मुक्त होना:

- जब मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी किसी बालक को प्राप्त करती है तो इसका प्रथम दायित्व जैविक माता-पिता का पता लगाना और बालक को उन्हें लौटा देना होता है। जैविक माता या पिता/माता और पिता से संबंधित एजेंसी द्वारा दत्तक ग्रहण के लिए उनकी सहमति और बालक की देखरेख और उसके भरण-पोषण के लिए उपलब्ध विकल्पों के संबंध में परामर्श दिया जाना और विधिवत सूचित किया जाना चाहिए। कोई भी एजेंसी सीधे या एजेंटों के माध्यम से जैविक माता-पिता को धन संबंधी तथा अन्य प्रलोभनों से उनके बालक का अभ्यर्पण करने के लिए उकसाने का प्रयास नहीं करेगी।

उपाय-3 देश में दत्तक ग्रहण को प्राथमिकता

- सभी दत्तक ग्रहण एजेंसियां देश में दत्तक ग्रहणों को प्राथमिकता देंगी जिससे कि प्रत्येक बालक को अपने स्वयं के सांस्कृतिक परिवेश में परिवार मिल सके। मान्यता प्राप्त स्थापन एजेंसी देश में ही किसी बालक का स्थापन करने के लिए 30 दिन के भीतर हर संभावना का पता लगाना चाहिए।
- प्रत्येक मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी, भारतीय बालकों के दत्तक ग्रहण पर विचार करते समय, निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम का पालन करने की अपेक्षा की जाती है:

1. भारत में रह रहे भारतीय नागरिक।
2. विदेश में रह रहे भारतीय नागरिक।
3. विदेश में भारतीय मूल के माता-पिता दोनों।*
4. विदेश में भारतीय मूल की माता या पिता।*
5. विदेशी परिवार।

(इस प्रयोजन के लिए अनिवासी भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति की परिभाषा ** में दी गई है)

उपाय - 4 प्रयासों का प्रलेखन:

प्रत्येक मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी प्रत्याशित दत्तक माता-पिता को (जैविक माता-पिता के नाम और पते को छोड़कर) बच्चे का पूरा ब्यौरा, जहां एजेंसी को जानकारी हो, देगी। प्रत्येक मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी भारतीय माता-पिता का पता लगाने के लिए किए गए प्रयासों का पूरा ब्यौरा तिथिवार रखेगी। देश में दत्तक ग्रहण में किसी बालक का स्थापन न किए जाने के कारणों को अभिलेखबद्ध किया जाना चाहिए। उन भारतीय परिवारों के नाम, पते और सम्पर्क नम्बर कारा, दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी तथा राज्य सरकार को, जब भी अपेक्षित हो, उपलब्ध कराए जाने चाहिए जिन्होंने बालक को स्वीकार नहीं किया है।

- जब प्राथमिकता एक के अनुसार बालक का स्थापन भारतीय माता-पिता के साथ करने के सभी प्रयास विफल हो जाएं, तब अध्याय-4 में यथानिर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

**** अनिवासी भारतीय का अभिप्रेत उस भारतीय नागरिक से है जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है और जो, इस समय, विदेश में रह रहा है।**

भारतीय मूल के व्यक्ति (पी आई ओ) का अभिप्रेत विदेशी नागरिक से है (जो पाकिस्तान, बंगला देश तथा अन्य देशों का नागरिक नहीं है जैसाकि केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए) यदि:

- (क) उसके पास किसी समय भारतीय पासपोर्ट रहा हो; या
- (ख) वह या उसके माता-पिता या दादा-दादी या परदादा-दादी में से कोई भारत में जन्मा हो और स्थायी रूप से भारत का तथा उन भू-भागों का निवासी हो जो उसके बाद भारत का हिस्सा बने, जैसाकि भारत सरकार अधिनियम, 1935 में परिभाषित है, बशर्ते कि उनमें से कोई किसी समय उपर्युक्त देशों (जैसाकि ऊपर दिया गया है) में से किसी का भी नागरिक नहीं रहा;
- (ग) वह भारत के नागरिक या उपर्युक्त (क) या (ख) के अंतर्गत शामिल भारतीय मूल के व्यक्ति का पति या पत्नी हो।

5.6 प्राधिकरणों को भेजे जाने वाले तिमाही आंकड़े:

प्रत्येक मान्यता प्राप्त भारतीय दत्तक ग्रहण स्थापन एजेंसी, उस क्षेत्र से संबंधित तिमाही आंकड़े राज्य सरकार को भेजेगी, जिसमें वह एजेंसी कार्य कर रही है तथा समय-समय पर दत्तक ग्रहण के लिए भारतीयों तथा अन्य को दिए गए बालकों के संबंध में तिमाही विवरण, केन्द्रीय दत्तक ग्रहण

संसाधन प्राधिकरण को केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित प्रपत्र में भेजेगी ।

5.7 बालक का अभ्यर्पण:

अभ्यर्पण दस्तावेज को जैविक माता-पिता/माता या पिता की ही इच्छा से निष्पादित किया जाना चाहिए और इसमें दत्तक ग्रहण एजेंसी की ओर से उनके लिए कोई दबाव, भुगतान या किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए । यदि जैविक माता या पिता/माता और पिता बालक के धार्मिक पालन-पोषण के तरजीह का उल्लेख करें तो यथासंभव उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए । परन्तु अन्ततः, बालक का दत्तक ग्रहण में रखे जाने से पूर्व, बालक का हित ही एकमात्र मार्गदर्शक कारक होगा ।

5.8 माता या पिता/माता और पिता को एजेंसी द्वारा अभ्यर्पण की तारीख से 60 दिन के अंदर वापस लेने के उसके/उनके अधिकार की जानकारी दी जानी चाहिए । उसे/उन्हें इस बात से अवगत कराया जाना चाहिए कि 60 दिनों की अवधि के बाद अभ्यर्पण प्रलेख अपरिवर्तनीय हो जाएंगे और बालक को दत्तक ग्रहण के लिए मुक्त समझा जाएगा तथा मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी बालक को दत्तक ग्रहण या संरक्षकता में भारत में या भारत से बाहर रखने के लिए स्वतंत्र होगी ।

5.9 निर्धारित स्टॉप पेपर में दो जिम्मेदार साक्षियों की उपस्थिति में अभ्यर्पण दस्तावेज निष्पादित किया जाएगा । इन साक्षियों से एक उत्तरदायी व्यक्ति होना चाहिए, जो संगठन का कर्मचारी न हो । दस्तावेजों पर नोटरी/शपथ आयुक्त द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाएंगे । मान्यता प्राप्त/लाइसेंस प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी, यदि आवश्यकता हो, इन साक्षियों को पेश करने में समर्थ होनी चाहिए । अभ्यर्पण दस्तावेज की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी एजेंसी पर होगी । एक अवयस्क द्वारा किसी बालक का अभ्यर्पण किए जाने की स्थिति में, उस नाबालिग के माता-पिता/रिश्तेदारों के हस्ताक्षर किए जाने चाहिए । माता-पिता में से एक उस नाबालिग के साथ हो । राज्य सरकार सभी अभ्यर्पण दस्तावेजों की क्रॉस जांच कर सकती है । अभ्यर्पण प्रक्रिया के दौरान, मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि:

1. यदि किसी बालक का अभ्यर्पण किया जाता है, तो माता-पिता दोनों को परित्याग संबंधी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने होते हैं और यदि

माता-पिता की मृत्यु हो गई हो तो मृत्यु प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाता है । जहां मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध न हो, वहां सरपंच/पंचायत/सरकारी प्राधिकरण से जारी प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जाना चाहिए;

2. एकल माता की स्थिति में, केवल वह स्वयं बालक का अभ्यर्पण कर सकती है कोई अन्य नहीं;
3. जहां बालक के जैविक माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, उसका अभ्यर्पण रिश्तेदारों द्वारा नहीं किया जा सकता और उसे एक परित्यक्त बच्चा/बच्ची समझा जाएगा और अपेक्षित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा;
4. जब किसी विवाहित दम्पति का बच्चा जन्म लेता है परन्तु जैविक माता या पिता में से किसी एक के द्वारा उसका अभ्यर्पण किया जाता है जबकि दूसरे का अता-पता नहीं होता है तो उसे एक परित्यक्त बच्चा समझा जाएगा तथा अपेक्षित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा;
5. यदि अभ्यर्पण के दस्तावेज को अवैध/अधूरा समझा जाता है तो उसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा जिसका अनुसरण एक परित्यक्त बालक के लिए किया जाता है; और
6. किसी भी अभ्यर्पण विलेख को राज्य सरकार की जांच के लिए भेजने का कारा को अधिकार होगा ।

5.10 परित्यक्त बालक

किसी परित्यक्त बालक को दत्तक ग्रहण के लिए मुक्त घोषित किए जाने संबंधी प्रक्रिया इस संबंध में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 तथा संबंधित राज्य के नियमों के संगत उपबंधों के अनुसार होगी ।

5.11 सूचना देना:

बालकों की स्थिति, भारतीय दत्तक ग्रहणों की संख्या और सभी पंजीकृत प्रत्याशित दत्तक माता-पिता की सूचियों के संबंध में मासिक विवरण दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी और राज्य सरकार के संबंधित विभाग को भेजा जाएगा । सभी मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसियां अपनी वार्षिक रिपोर्टें, परीक्षित लेखा विवरण तथा एफ सी आर ए की प्रति कारा को भेजेंगी जिसमें दत्तक ग्रहण शुल्क, दान तथा अवधि के दौरान गोद लिए गए बालकों से संबंधित आंकड़ों आदि का विवरण हो ।

5.12 बालकों का हस्तांतरण:

बालक को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा जैसाकि इस संबंध में किशोर न्याय अधिनियम, 2000 या संबंधित राज्य किशोर न्याय नियमों में लागू है। सभी हस्तांतरण संबंधी मामलों की सूचना दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी की दी जानी चाहिए। ऐसे सभी बालकों को, जो गैर-मान्यता प्राप्त एजेंसियों से मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी (कारा, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त) को चाहे वे राज्य के अंदर या उसके बाहर हस्तांतरित होते हैं, विदेश में दत्तक ग्रहण के लिए कोई कार्रवाई आरंभ करने से पूर्व, कम से कम एक माह की अवधि के लिए मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी की वास्तविक अभिरक्षा में होना चाहिए। यह एक ही संगठन के उप कार्यालयों से बालकों के हस्तांतरण की स्थिति में भी लागू है।

5.13 बालक के हस्तांतरण के साथ उसके दाखिले, प्रारंभिक इतिवृत्त, दस्तावेजी प्रमाण, जिससे यह सिद्ध हो कि वह बालक दत्तक ग्रहण के लिए मुक्त है, से संबंधित उपलब्ध दस्तावेज होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, बालक का फोटोग्राफ, सी एस आर, पी ई आर तथा अन्य संगत दस्तावेज भेजे जाने चाहिए। मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी को बालक को स्वीकार करने से पहले सभी तथ्यों का सत्यापन कर लेना चाहिए क्योंकि वह बालक के स्थापन के लिए कानूनन उत्तरदायी है।

5.14 बालकों के अन्तर्राज्यीय हस्तांतरण के मामले में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए:

- (क) अनाथालय/एजेंसी से किसी दूसरे राज्य में बालकों का हस्तांतरण राज्य सरकार की अनुमति से किया जा सकता है;
- (ख) बालक को नजदीकी दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी के पास पंजीकृत होना चाहिए तथा दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी निर्धारित अवधि के भीतर उपयुक्त भारतीय माता-पिता को ढूँढ़ने के सभी संभव प्रयास करेगी; और
- (ग) यदि बालक के मूल राज्य में कोई दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी नहीं हो तो दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी पंजीकरण उस राज्य में होना चाहिए जिसमें बालक का हस्तांतरण किया गया है।

5.15 अनुवर्ती कार्रवाई:

मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी, अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्टें सूचीबद्ध विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी से नियमित रूप से प्राप्त करेगी और किसी बालक के बारे में किसी विघटन या नकारात्मक सूचना के बारे में कारा को सूचित करेगी । यह देश में दत्तक ग्रहण संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार देश में दत्तक ग्रहण में रखे गए बालकों की प्रगति रिपोर्टों को भी मानीटर करेगी ।

5.16 रिकार्ड:

प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्थापन एजेंसी/लाइसेंस प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी द्वारा निम्नलिखित रिकार्ड और रजिस्टर रखे जाने चाहिए:

1. यथा निर्धारित मास्टर प्रवेश रजिस्टर;
2. निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक बालक के बारे में एक पृथक फाइल, जिसमें पूर्ण ब्यौरा/पूर्ववृत्त दिया गया हो । प्रत्येक दत्तक ग्रहण के संगत कानूनी दस्तावेज तथा बालक की पृष्ठभूमि/इतिवृत्त कम से कम 18 वर्षों तक भावी संदर्भ के लिए रखा जाना चाहिए । फाइल में अन्य संबंधित सूचना अर्थात् प्रतिरक्षण चार्ट, चिकित्सा का विवरण आदि होना चाहिए;
3. प्रत्याशित भारतीय, अनिवासी भारतीय तथा विदेशी दत्तक माता-पिता के पूर्ण विवरण का एक अलग रजिस्टर;
4. देश में तथा देश से बाहर दत्तक ग्रहण में रखे गए बालकों के लिए अलग अनुवर्ती रजिस्टर;
5. निर्धारित प्रपत्र में तिमाही रिपोर्टें जो राज्य सरकार, केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण और दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी को भेजी जाती हैं;
6. संगठन की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें इसके दत्तक ग्रहण तथा अन्य समाज और बाल कल्याण संबंधी कार्यकलापों का स्पष्ट उल्लेख हो;
7. परीक्षित लेखा विवरण के साथ गृह मंत्रालय को भेजी गई एफ सी आर ए लेखे की एक प्रति; और
8. सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 या सार्वजनिक न्यासों से संबंधित संगत राज्य कानून के अधीन निर्धारित अन्य रिकार्ड ।

5.17 देश से बाहर दत्तक ग्रहण की स्थिति में लागत की वसूली:

(क) संगठन केवल लाभ-मुक्त उद्देश्यों पर चलेगा । इसे किसी भी परिस्थिति में देश से बाहर या देश में दत्तक ग्रहण से संबंधित किसी कार्यकलाप से अनुचित वित्तीय लाभ प्राप्त नहीं करना चाहिए । देश से बाहर दत्तक ग्रहण में, 3500 अमेरिकी डालर या भारतीय रुपयों में इसके समतुल्य नियत राशि की दत्तक ग्रहण फीस सूचीबद्ध विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी या किसी केन्द्रीय प्राधिकरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसियों को दत्तक माता-पिता द्वारा दी जाएगी । इस फीस में स्तरीय बाल देखरेख, चिकित्सा एवं कानूनी सेवाएं, पासपोर्ट, वीजा, व्यावसायिक स्टाफ के लिए भुगतान, मानीटरिंग, पत्राचार, बाल अध्ययन रिपोर्टों को तैयार करने, चिकित्सा रिपोर्टें आदि उपलब्ध कराने की लागत शामिल है । वसूली योग्य खर्चों की इस बाहरी सीमा की समीक्षा कारा/भारत सरकार द्वारा, रहन-सहन की लागत सहित खर्च बढ़ जाने पर पांच वर्षों में एक बार की जाएगी । दत्तक ग्रहण में विघटन या विफलता की स्थिति में यदि मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी की सहमति से विदेशी के देश में, बालक का कोई वैकल्पिक स्थापन नहीं हो पाता है तो बालक को भारत में वापस लाने की लागत का वहन सूचीबद्ध विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी द्वारा किया जाएगा ।

(ख) किसी मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी द्वारा किसी विदेशी प्रत्याशित दत्तक माता या पिता/माता और पिता या सूचीबद्ध विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी से कोई दान प्राप्त नहीं किया जाएगा:

1. यदि कारा के ध्यान में यह बात आती है कि कोई मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी निर्धारित फीस से अधिक लेती है या प्रायोजित करने वाली एजेंसी/दत्तक माता-पिता का वित्तीय रूप से शोषण करती है तो कारा ऐसी एजेंसी को स्थिति स्पष्ट करने का मौका देने के बाद इसकी मान्यता को समाप्त कर सकता है या वापस ले सकता है या कानून के अनुरूप अर्थात् चूककर्ता पाए गए व्यक्ति के लिए जवाबदेही के सिद्धांतों के अनुसार राज्य सरकार को आपराधिक अभियोजन की सिफारिश कर सकता है । इसी प्रकार, यदि कोई सूचीबद्ध विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी, किसी भारतीय बालक के देश से

बाहर दत्तक ग्रहण की स्थिति में, किसी मामले में कार्रवाई करने के लिए मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी को निर्धारित फीस से अधिक धनराशि के प्रस्ताव देकर उकसाती है, तो कारा ऐसी एजेंसी को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करने के बाद, उस विदेशी एजेंसी को सूची से बाहर करने के साथ-साथ उस देश के कानून के अनुसार चूककर्ताओं पर मुकदमा चलाने की सिफारिश कर सकता है; और

2. भारतीय और विदेशी एजेंसियों के मध्य विदेशी परिवारों को दत्तक ग्रहण के लिए दिए जाने वाले बालकों की संख्या के संबंध में कोई करार (समझौता) नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार, इस तरह का करार दान एवं फीस के संबंध में ऐसी एजेंसियों के मध्य निष्पादित नहीं किया जाएगा।

5.18 मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी की मान्यता का नवीकरण:

मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी को, पूर्ववर्ती मान्यता की समाप्ति की तारीख से 6 माह पहले, मान्यता के नवीकरण के लिए आवेदन करना चाहिए। एजेंसी द्वारा मूल आवेदन राज्य सरकार के उपयुक्त प्राधिकरण को भेजा जाना चाहिए और साथ ही उसकी प्रति सीधे कारा को भेजी जानी चाहिए। राज्य सरकार मूल आवेदन को अपनी टिप्पणियों के साथ पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर कारा को अग्रेषित करेगी। यदि राज्य सरकार आवेदन प्राप्ति की तारीख से तीन माह के अंदर उत्तर नहीं देती है, तो कारा एक संयुक्त निरीक्षण करेगा और मान्यता के नवीकरण पर विचार करेगा। मान्यता का नवीकरण सामान्य तौर पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा :

- (क) संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश/विचार जिसके साथ एजेंसी की निरीक्षण रिपोर्ट है;
- (ख) किसी मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी की मान्यता का आगे नवीकरण का जायजा लेने और विचार करने के लिए देश में दत्तक ग्रहण से संबंधित संतोषप्रद कार्य-निष्पादन एक महत्वपूर्ण कारक होगा। एजेंसियां देश में दत्तक ग्रहण के क्षेत्र में अपने कार्य को पर्याप्त रूप से दर्शाएंगी। एजेंसियां भारत में भारतीयों को दत्तक ग्रहण में 50% या उससे अधिक बालकों का स्थापन करेंगी;

- (ग) वार्षिक रिपोर्ट, एजेंसियों की तिमाही रिपोर्टें तथा यथा निर्धारित संपरीक्षित लेखा विवरण, प्रति बालक दत्तक ग्रहण प्रभार, प्राप्त दान, यदि कोई हो, को नियमित रूप से भेजना;
- (घ) मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी के खिलाफ प्रमाणित अनाचार का कोई उदाहरण नहीं होना;
- (ङ.) क्या एजेंसी संगत नियमों के अंतर्गत बाल गृह संचालित करने और देश में दत्तक ग्रहण कार्य करने के लिए संबंधित राज्य सरकार के उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा अभी भी मान्यता प्राप्त है; और
- (च) प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के समर्थन में तीन वर्षों की अवधि के लिए देश में दत्तक ग्रहण और देश से बाहर दत्तक ग्रहण में रखे गए बालकों की वर्षवार सूची ।

5.19 एजेंसियों द्वारा लेखा रखा जाना:

1. हर एजेंसी उपयुक्त लेखाओं को बनाए रखेगी जिनकी प्रत्येक वर्ष चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा लेखा परीक्षा कराएगी;
2. लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ संपरीक्षित लेखाओं की एक सत्यापित प्रति संबंधित राज्य सरकार के प्रासंगिक विभाग तथा कारा को चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा लेखाओं की लेखा परीक्षा किए जाने की तारीख से एक माह के भीतर प्रत्येक एजेंसी द्वारा भेजी जाएगी; और
3. एजेंसी द्वारा, गृह मंत्रालय को भेजे गए एफ सी आर ए लेखाओं की सत्यापित प्रति संपरीक्षित लेखों के साथ कारा को भेजी जानी चाहिए । विभिन्न स्रोतों से प्राप्त दत्तक ग्रहण प्रभार और दान संबंधी सूचना कारा को प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में भेजी जाएगी ।

5.20 मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसियों का केवल सूचीबद्ध विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसियों के साथ कार्रवाई करना:

कोई भी मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी विदेशियों { अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों सहित) (जो लागू हो) } से किसी भारतीय बालक के दत्तक ग्रहण के लिए किसी आवेदन पर उस समय तक कार्रवाई नहीं करेगी जब तक कि सूचीबद्ध विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी/केन्द्रीय प्राधिकरण या उपयुक्त सरकारी प्राधिकरण/उन देशों के विधिवत प्राधिकृत निकाय जहां कोई सूचीबद्ध एजेंसी नहीं हो, के माध्यम से अग्रेषित नहीं की गई हो । मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी को किसी विदेशी व्यक्ति या विदेशी एजेंसी, जो कारा द्वारा सूचीबद्ध नहीं हो, से प्राप्त आवेदन पर सीधे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए ।

5.21 एजेंसियों का निरीक्षण:

कारा, राज्य सरकार या कारा द्वारा प्राधिकृति किसी अन्य एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसियों के बाल गृहों सहित उनके अभिलेखों का निरीक्षण किसी भी समय किया जा सकेगा।

5.22 मान्यता समाप्त करना:

कारा द्वारा, जहां कहीं आवश्यकता पड़े, कारण बताओ नोटिस जारी करके एजेंसी को उचित अवसर देने के बाद, मान्यता वापस ली जा सकती है या समाप्त की जा सकती है। कोई मान्यता स्थाई आधार पर प्रदान नहीं की जाती है और वह समय-समय पर समीक्षा के अधीन होगी।

5.23 रक्षोपाय

1. विदेशी प्रत्याशित दत्तक माता-पिता और जैविक माता-पिता के मध्य किसी सम्पर्क की अनुमति नहीं दी जाएगी। दत्तक ग्रहण एजेंसी द्वारा जैविक माता/माता-पिता को परामर्श सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी चाहिए। बालक के जन्म से पूर्व, जैविक माता की सहमति प्राप्त नहीं की जा सकता;
2. अनिवासी भारतीयों के मामले को छोड़कर, दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी की स्वीकृति से पूर्व, देश से बाहर दत्तक ग्रहण के लिए किसी बालक का प्रस्ताव नहीं किया जाना चाहिए;
3. मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी बालक के मूल, उसके माता-पिता की गोपनीयता को बनाए रखेगी;
4. कोई भी व्यक्ति दत्तक ग्रहण से संबंधित किसी कार्यकलाप से अनुचित वित्तीय लाभ या अन्य फायदा प्राप्त नहीं करेगा। की गई किसी भी सेवा के लिए दिए गए भुगतान की स्थिति में रसीद जारी की जाएगी;
5. किसी विदेशी प्रत्याशित दत्तक माता-पिता द्वारा कोई सीधा दत्तक ग्रहण नहीं किया जा सकता तथा ऐसे सभी दत्तक ग्रहण मान्यता प्राप्त/सूचीबद्ध एजेंसियों के माध्यम से होंगे जैसा कि दिशा-निर्देशों में परिभाषित है;
6. मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसियां कठोर नैतिक प्रक्रियाओं का पालन करेगी और बालकों के सर्वोत्तम हित में कार्य करेगी जैसाकि दिशा-निर्देशों में परिभाषित है और जिसका वर्णन देश से बाहर दत्तक ग्रहण संबंधी हंग कन्वेंशन, 1993 में किया गया है, जिसके न होने पर चूककर्ता एजेंसी/एजेंसियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की

जाएगी। एजेंसी/एजेंसियों के पदाधिकारी प्रक्रिया संबंधी रक्षा-उपायों को तोड़ने या नैतिक प्रक्रियाओं का पालन न करने के जिम्मेवार होंगे।

अध्याय - 6

दत्तक ग्रहण के लिए सूचीबद्ध विदेशी एजेंसियां (ई एफ ए ए)

6.1 विदेशी एजेंसियों का भारत के राजनयिक मिशनों को आवेदन करना:

किसी भारतीय बालक को गोद लेने के लिए विदेशी दत्तक माता-पिता के आवेदनों को प्रायोजित करने की इच्छुक विदेशी समाज/बाल कल्याण एजेंसी उस देश में भारतीय राजनयिक मिशन के कार्यालय के माध्यम से प्राधिकार के लिए कारा को आवेदन करेगी और कारा द्वारा इस प्रयोजन के लिए केवल सूचीबद्ध इस प्रकार की विदेशी एजेंसियां ही यह कार्य करेंगी।

6.2 विदेशी एजेंसियों को सूचीबद्ध करने के मानदंड:

देश से बाहर दत्तक ग्रहण के प्रयोजन के लिए, कारा द्वारा विदेशी एजेंसियों को सूचीबद्ध/प्राधिकृत करने संबंधी मानदंड इस प्रकार हैं :

1. यह संबंधित देश के संगत कानून के अधीन विधिवत् पंजीकृत एक एजेंसी होगी और देश से बाहर दत्तक ग्रहण करने के लिए उस देश के उचित प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त/लाइसेंस प्राप्त होनी चाहिए;
2. यह सक्षम प्राधिकरण द्वारा देश से बाहर दत्तक ग्रहण संबंधी हेग कन्वेंशन, 1993 (जहां लागू हो) के अधीन विधिवत् मान्यता प्राप्त और प्राधिकृत होनी चाहिए;
3. यह संगम ज्ञापन, मिशन स्टेटमेंट, पंजीकरण स्थिति की प्रतियां, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण कार्य करने के लिए संबंधित सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी अद्यतन लाइसेंस, बोर्ड/कार्यकारिणी के सदस्यों की सूची तथा जिन देशों के साथ यह कार्य कर रही है उनकी सूची प्रस्तुत करेगी;
4. यह एक बाल कल्याण एजेंसी होगी और इस क्षेत्र में इसकी एक सुव्यवस्थित स्थिति होगी तथा इसमें योग्य सामाजिक कार्यकर्ताओं का स्टाफ होना चाहिए जिन्हें दत्तक ग्रहण के क्षेत्र में अनुभव हो। यह

- संगठन के कार्यकलापों, गत 3 वर्ष की वार्षिक रिपोर्टों, कर्मचारियों की उनकी योग्यता सहित सूची तथा गत दो वर्षों के लेखे प्रस्तुत करेगी;
5. यह एजेंसी गैर-वाणिज्यिक और लाभ रहित आधार पर चलेगी तथा भारतीय एजेंसियों को किए गए भुगतान के संबंध में वार्षिक विवरण उपलब्ध कराएगी;
 6. सूचीबद्ध विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी एक वचनबंध कि दत्तक ग्रहण के प्रभाव में आने से पूर्व यदि विदेशी के परिवार के विघटन की स्थिति में दत्तक परिवार में बालक की उचित प्रकार से देखरेख नहीं होती और उससे अच्छा बरताव नहीं किया जाता अथवा उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तो यह भारतीय राजनयिक मिशन, केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, संबंधित मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी को तत्काल पूरे ब्यौरे के साथ और बालक की देखरेख और संरक्षण के लिए की गई कार्रवाई के बारे में सूचित करते हुए बालक के देखरेख की जिम्मेदारी लेगी । इस मामले में कार्रवाई करने वाली मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी की सहमति से बालक के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थापन प्राप्त करना और भारतीय न्यायालय, जिसने संरक्षकता के लिए आदेश किए, को ऐसे वैकल्पिक स्थापन की सूचना देना शामिल है । इस प्रकार के मामले में जिसमें बालक का भारत को वापस या तो उसके जैविक परिवार या मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी या किसी अन्य संगठन को लाया जा रहा हो, वहां कारा से परामर्श किया जाना चाहिए । सभी सामाजिक और चिकित्सीय रिपोर्टें दी जाएं । बालक की कानूनी स्थिति, विदेशी मुल्क में उसके नागरिक का अधिकार तथा दत्तक माता-पिता के कानूनी दायित्वों का उल्लेख किया जाना चाहिए । बालक की देखरेख योजना तैयार की जाएगी और राज्य सरकार या कारा द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य संगठन बालक के कल्याण को मानीटर करेगा । विदेश से वापसी तथा पश्चातवर्ती देखरेख सहित सम्पूर्ण लागत का वहन सूचीबद्ध विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी करेगी;
 7. संगठन का प्रमुख/मुख्य कार्यपालक दिशा-निर्देशों का अनुसरण करने, अपेक्षित प्रगति रिपोर्टें भेजने, दत्तक डिक्री की एक प्रति भेजने के लिए एक लिखित वचनबंध देने का रजामंद होना चाहिए; और
 8. विदेशी सरकार के संबंधित विभाग/केन्द्रीय प्राधिकरण, जो उपर्युक्त वचनबंध देने के लिए सहमत हों, को विदेशी नागरिकों के आवेदनों को

प्रायोजित करने के उद्देश्य से सूचीबद्ध एजेंसियों के रूप में समझा जाएगा । केन्द्रीय प्राधिकरणों को कारा के साथ सूचीबद्ध होने के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है ।

6.3 सूचीबद्धता की प्रक्रिया:

1. भारतीय बालकों को गोद लेने के लिए विदेशी दत्तक माता-पिता के आवेदनों को प्रायोजित करने की इच्छुक विदेशी समाज/बाल कल्याण एजेंसी, कारा के साथ सूचीबद्ध किए जाने के लिए भारतीय राजनयिक मिशन के कार्यालय तथा जिस देश में यह स्थित है वहां की सरकार के माध्यम से कारा को आवेदन करेगी;
2. संबंधित देश में भारत के राजनयिक मिशन की सिफारिश पर, कारा सूचीबद्ध करने संबंधी आवेदन की जांच करेगा और सूचीबद्ध किए जाने के लिए संबंधित एजेंसी पर विचार करेगा बशर्ते कि वह उपर्युक्त पैराग्राफ 6.2 में उल्लिखित मानदंडों को पूरा करती हो; और
3. एक विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी को 5 वर्ष की अवधि के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है ।

6.4 सूचीबद्धता का नवीकरण:

1. संतोषजनक कार्य निष्पादन और इसकी सूचीबद्धता से संलग्न निबंधन एवं शर्तों के अधीन सूचीबद्धता का नवीकरण 5 वर्ष के लिए होगा; और
2. प्रत्येक सूचीबद्ध विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी, सूचीकरण नवीकरण के लिए पूर्ववर्ती मान्यता की समाप्ति की तारीख से 6 माह पहले संबंधित भारतीय राजनयिक मिशन के माध्यम से कारा को आवेदन करे ।

6.5 सूचीबद्धता से अलग किया जाना:

केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार किसी विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी को दत्तक ग्रहण के लिए लिखित में अभिलेखबद्ध किए जाने के वैध या विधिसंगत कारणों से किसी भी समय सूची से अलग कर सकता है । परन्तु, यदि सूची से बाहर किए जाने के समय कोई ऐसा मामला प्रक्रियाधीन हो जिसे पूर्ण किए जाने की

अनुमति दी जाए, जब तक कि कारा यह निर्णय नहीं कर लेता कि ऐसा करना बालक के सर्वोत्तम हित में नहीं होगा। नियमित रूप से प्रगति रिपोर्टें न भेजना, सूची से बाहर किए जाने का कारण बन सकता है।

6.6 अनुवर्ती रिपोर्ट:

(क) सूचीबद्ध विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी/केन्द्रीय प्राधिकरण प्रत्येक बालक के संदर्भ में बालक के फोटोग्राफों के साथ अनुवर्ती रिपोर्टें दो वर्ष की अवधि के लिए या ऐसे समय तक जब तक कि कानूनी दत्तक ग्रहण पूर्ण नहीं हो जाता है और प्राप्तकर्ता देश में नागरिकता प्राप्त नहीं हो जाती है, छःमाही आधार पर निम्नलिखित को भेजेगा:

1. कारा;
2. न्यायालय जिसने भारत में संरक्षकता प्रदान की है;
3. भारतीय दूतावास; और
4. संबंधित मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी।

(ख) सूचीबद्ध विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी/केन्द्रीय प्राधिकरण उस देश में उचित प्राधिकरण के कानूनी दत्तक ग्रहण आदेश की एक प्रति, ज्यों ही यह आदेश किया जाता है, निम्नलिखित को भेजेगा:

1. कारा; और
2. न्यायालय जिसने भारत में संरक्षकता प्रदान की है।

(ग) जहां बालक को प्राप्तकर्ता राज्य में दत्तक माता-पिता द्वारा या तो परिवार में विघटन के कारण या बालक के व्यवहार के प्रति समायोजित होने में विफल होने या किन्हीं अन्य कारणों से दत्तक माता-पिता को संरक्षकों के रूप में नियुक्त करने वाले भारत के न्यायालय के आदेश की तारीख से दो वर्ष के भीतर कानूनी रूप से गोद नहीं लिया गया हो, तो सूचीबद्ध विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी, जिसने प्राप्तकर्ता देश में बालक के दत्तक ग्रहण की कार्रवाई की है, को बालक को तत्काल दत्तक माता-पिता से वापस ले लेना चाहिए और बालक को अपनी अभिरक्षा और देखरेख में रख लेना चाहिए और जितना जल्दी संभव हो सके दत्तक ग्रहण में बालक के स्थापन के लिए नए दत्तक माता-पिता

का पता लगाना चाहिए । विदेशी एजेंसी इस आशय का एक वचनबंध भारत में मामले में कार्रवाई करने वाले न्यायालय को देगी ।

- 6.7 प्राप्तकर्ता देश में सूचीबद्ध विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी या केन्द्रीय प्राधिकरण भारतीय मूल के बालकों और उनके दत्तक माता-पिता का सम्मेलन समय-समय पर आयोजित करेंगे और संबंधित भारतीय राजनयिक मिशनों को भी शामिल करेंगे ।

* * * *

अध्याय - 7

विदेश में भारतीय राजनयिक मिशनों की भूमिका

- 7.1 विभिन्न देशों में स्थित भारतीय मिशन, भारतीय बालकों का देश से बाहर दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । ये मिशन अपने क्षेत्राधिकार वाले देशों में कार्य कर रहे अनेक प्राधिकरणों और एजेंसियों के साथ सम्पर्क बनाए रखने में कारा की सहायता करेंगे । इन मिशनों के लिए परिकल्पित भूमिका मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आती है:-
1. नई सूचीबद्धता और उसके बाद भारत के साथ कार्य करने की इच्छुक विदेशी एजेंसियों के नवीकरण के लिए सिफारिश; और
 2. प्रत्याशित दत्तक माता-पिता के डोजियर/दस्तावेजों का सत्यापन, जिन्हें विदेशी प्राधिकरणों/एजेंसियों द्वारा कारा को भेजने से पूर्व, प्रस्तुत किया जाता है (जहां कहीं विदेशी लोक दस्तावेजों के लिए वैधीकरण की अपेक्षा समाप्त करने संबंधी 1961 का हेग कन्वेंशन लागू नहीं होता है) ।
- 7.2 जबकि नई सूचीबद्धता के लिए सिफारिशें केवल संबंधित भारतीय दूतावास/उच्चायोग के द्वारा की जानी चाहिए, नवीकरण की स्थिति में उसकी सिफारिश कांसूलेट जनरल्स तथा डिप्टी हाई कमीशनों के कार्यालयों द्वारा की जा सकती हैं ।
- 7.3 किसी देश में निवास कर रहे भारतीय पासपोर्ट धारकों के मामले में, जहां कोई सूचीबद्ध एजेंसी नहीं है या जहां स्थानीय कानूनों के अनुसार, मेजबान

सरकार द्वारा उनकी सिफारिश नहीं की जा सकती है, वहां भारतीय दूतावास एक योग्य सामाजिक कार्यकर्ता को गृह अध्ययन रिपोर्ट तथा प्रगति रिपोर्ट आदि भेजने के लिए वचनबंध सहित अन्य दस्तावेजों और अपनी सिफारिश के साथ कारा को डोजियर भेजने के लिए प्राधिकृत कर सकती है।

- 7.4 जब कभी किसी विदेशी दम्पति द्वारा भारतीय बालक के दत्तक ग्रहण विघटन रिपोर्ट प्राप्त हो तो दूतावास को स्थानीय केन्द्रीय प्राधिकरण तथा अन्य संबंधित प्राधिकरणों से यह सुनिश्चित करने के लिए सम्पर्क करना चाहिए कि बालक के हित की देखभाल की जाती है। इस संबंध में कारा को भी एक रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र भेजी जानी चाहिए।

बालक को भारत को लौटाने की अपेक्षा की स्थिति में, दूतावास स्थानीय प्राधिकरणों, एजेंसी और कारा के परामर्श से आवश्यक सहायता करेगा और बालक की वापसी को आसान बनाएगा।

- 7.5 दूतावास को किसी ऐसी सूचना और टिप्पणी को कारा को भेज देना चाहिए जिसे वे महसूस करें कि देश से बाहर दत्तक ग्रहण की दृष्टि से वे महत्वपूर्ण और संगत हैं।

- 7.6 दस्तावेजों के सत्यापन के समय, दूतावास को यदि दस्तावेज अंग्रेजी के स्थान पर अन्य भाषा में भेजे जाते हैं, तो उसका अधिप्रमाणित अंग्रेजी अनुवाद शामिल किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

* * * *

अध्याय - 8

दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी (ए सी ए)

- 8.1 किसी राज्य में या विशेष परिस्थितियों में राज्यों के समूह के लिए, जहां दिशा-निर्देशों के अधीन तथा इसे कारा द्वारा समय-समय पर सौंपे गए निर्धारित कार्यों को सम्पन्न करने के लिए अनेक बाल गृह और दत्तक ग्रहण एजेंसियां हैं, एक दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी (ए सी ए) होगी।

8.2 दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या विस्तृत नियमों और विनियमों से राज्य सरकार द्वारा सृजित किए गए प्राधिकरण के अधीन पंजीकृत होगी तथा अधिनियम और दिशा निर्देशों में निर्धारित सभी नियमों का पालन करेगी।

8.3 कृत्यः

1. दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी समय-समय पर ऐसे बालकों की सूची प्राप्त करेगी जो निम्नलिखित से प्रत्येक माह दत्तक ग्रहण के लिए मुक्त हैं और उसके लिए एक रजिस्टर रखेगी:
 - (क) मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसियां;
 - (ख) लाइसेंस प्राप्त दत्तक ग्रहण स्थापन एजेंसियां;
 - (ग) सरकारी गृह; और
 - (घ) अन्य बाल गृह।
2. यह भारतीय दत्तक ग्रहण के क्षेत्र में अपनी सभी सदस्य एजेंसियों तथा अन्य बाल कल्याण संस्थाओं के कार्य का समन्वय करेगी।
3. यह संगम ज्ञापन के अनुसार सदस्यों की आवधिक बैठक आयोजित करेगी और प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बैठक करेगी।
4. यह उन बच्चों का ब्यौरा प्राप्त करेगी जिनकी मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसियों से देश से बाहर दत्तक ग्रहणों के लिए मुक्त किए जाने की मांग की जा रही है और यह सुनिश्चित करेगी कि देश के भीतर दत्तक ग्रहण के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित प्राथमिकता का पालन किया जाए।
5. यह प्रत्याशित भारतीय दत्तक माता-पिता को पंजीकृत करेगी और जहां जरूरी हो, भावी भारतीय दत्तक माता-पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करेगी।
6. यह सदस्य एजेंसियों से प्रत्याशित भारतीय दत्तक माता-पिता की एक नई सूची भी प्राप्त करेगी।
7. यदि तीसवें दिन के अंत में कोई उपयुक्त दत्तक माता-पिता नहीं मिले, तो दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी विदेशी दत्तक माता-पिता के पास रखे जाने वाले बालक को देखने एवं सभी संगत दस्तावेजों की जांच करने के बाद उनकी सहायता में रखे गए बालक को एक अनुमति प्रमाण-पत्र देगी। इस अनुमति प्रमाणपत्र में बालक का अद्यतन फोटोग्राफ शामिल होना चाहिए।

8. उन मामलों में, जहां किसी मान्यता प्राप्त/लाइसेंस प्राप्त एजेंसी द्वारा कारा के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा हो वहां दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी इसे राज्य सरकार और कारा के ध्यान में लाएगी।
9. दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी को देश में दत्तक ग्रहण को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम शुरू करने चाहिए।
10. दत्तक ग्रहण कार्यकर्ताओं के कौशलों के उन्नयन के लिए इसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए।
11. जहां कहीं आवश्यक हो, इसे दत्तक ग्रहणपूर्व और दत्तक ग्रहण पश्चात् के परामर्श उपलब्ध करने चाहिए।
12. दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी स्तरीय बाल देखरेख, स्वास्थ्य एवं आरोग्यता के पालन को स्थापन एजेंसी में बढ़ावा देगी। किसी अनियमितता या बालकों की उपेक्षा की सूचना कारा को दी जानी चाहिए।
13. सभी दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसियां कारा को वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षित विवरण और वर्ष भर किए गए कार्यकलापों की सूचना भेजेंगी।
14. यह कारा को केन्द्रीय पूल तैयार करने के लिए दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी की सहायता से बच्चों के स्थापन पर नियमित सूचना भेजेगी।
15. दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी, कारा द्वारा समय-समय पर यथा निर्देशित दत्तक ग्रहण के क्षेत्र में अन्य कार्यों को करेगी।
16. दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी निर्धारित अवधि के भीतर देश से बाहर दत्तक ग्रहण में स्थापन के लिए बालक को अनुमति प्रमाणपत्र जारी करने से पहले, अन्तर-स्वैच्छिक समन्वय एजेंसी समन्वय के माध्यम से देश में दत्तक ग्रहण में किसी बालक को रखने के सभी संभव प्रयास करेगी।

8.4 दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी में कम से कम दो व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित कर्मचारी होंगे।

8.5 मान्यता:

प्रत्येक मान्यता प्राप्त दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी को मान्यता के नवीकरण के लिए पूर्ववर्ती मान्यता की समाप्ति की तारीख से 6 माह पूर्व आवेदन करना चाहिए।

(क) मान्यता, सामान्य तौर पर, तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी। कारा किसी खास दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी के कार्य-निष्पादन के आधार पर, 3 वर्ष से कम के लिए मान्यता दे सकेगी।

(ख) मान्यता के लिए मानदंड:

दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए, एजेंसी निम्नलिखित मानदंड पूरा करे :

1. यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या विस्तृत नियमों और विनियमों के साथ संबंधित राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी प्राधिकरण के अधीन एक सोसाइटी हो;
2. कारा द्वारा मान्यता के लिए, एजेंसी की सिफारिश संबंधित राज्य सरकार द्वारा की जानी चाहिए;
3. एजेंसी गैर-वाणिज्यिक तथा लाभ रहित आधार पर चलनी चाहिए;
4. कारा के दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए वचनबंध; और
5. सभी पदाधिकारी भारतीय नागरिक हो ।

(ग) मान्यता का नवीकरण:

दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी मान्यता के लिए अनुरोध करती है, इसलिए इसे पूर्ववर्ती मान्यता की समाप्ति की तारीख से छः माह पूर्व, मान्यता के नवीकरण के लिए राज्य सरकार के माध्यम से कारा को आवेदन करना चाहिए । यदि राज्य सरकार आवेदन प्राप्ति की तारीख से 60 दिन की निर्धारित अवधि के अंदर उत्तर नहीं दे पाती है, यह मान लिया जाएगा कि राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है । तथापि, कारा तथा राज्य सरकार के संयुक्त निरीक्षण के बाद, कारा मान्यता जारी कर सकता है । मान्यता के नवीकरण के लिए, मुख्य मानदंड निम्नलिखित होंगे:

1. देश में दत्तक ग्रहण के प्रोत्साहन में संतोषजनक कार्य-निष्पादन;
2. रिपोर्टों और परीक्षित लेखा विवरण समय पर प्रस्तुत करना जैसा कि कारा द्वारा निर्दिष्ट किया गया है; और
3. दिशा-निर्देशों का पालन ।

(घ) मान्यता वापस लेना:

कारा द्वारा दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करने के बाद, इन दिशानिर्देशों में दिए गए निबंधन एवं शर्तों के उल्लंघन के लिए कारा द्वारा दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी

की मान्यता वापस ली जा सकती है। कोई भी अनाचार, यदि सिद्ध हो जाए, मान्यता वापस लेने के रूप में तत्काल कार्रवाई को आमंत्रित करेगा। राज्य सरकार या कारा द्वारा मांगी गई रिपोर्ट/लेख भेजे जाने में विलम्ब करने और अनुपालन न करने से भी मान्यता को वापस लेने का आधार बनेगा।

मान्यता वापस लेने की स्थिति में, कारा अनुमति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक तंत्र तैयार करेगा।

8.6 दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी की सदस्यता:

सभी मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसियों, लाइसेंस प्राप्त दत्तक ग्रहण एजेंसियों, शिशु गृहों और सरकार द्वारा चलाए जा रहे बाल गृहों को किसी दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी के सदस्य बनना अपेक्षित होगा। बाल कल्याण एजेंसियां, जो बालकों को दत्तक ग्रहण में नहीं रख रही हैं परन्तु बालकों के लिए गृह आदि चला रही हैं, भी दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी के सदस्य बनने की पात्र हैं। कारा द्वारा मान्यता समाप्त की गई या राज्य लाइसेंस वापस ली गई कोई एजेंसी किसी दत्तक ग्रहण एजेंसी का सदस्य नहीं बनी रहेगी और जब तक कि यह एक बार फिर मान्यता प्राप्त और लाइसेंस प्राप्त नहीं कर लेती, यह किसी दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी की सदस्यता के लिए पात्र नहीं रहेगी। दत्तक माता-पिता संघ भी सदस्यता के पात्र होंगे। दत्तक ग्रहण/बाल कल्याण में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में लिया जा सकता है। उपर्युक्त से दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी की साधारण सभा बनेगी।

8.7 दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी की संरचना:

दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी के कार्यों के प्रबंधन के लिए एक कार्यकारिणी समिति होगी। कार्यकारिणी समिति में 5 से कम सदस्य नहीं होंगे। केवल कारा द्वारा मान्यता प्राप्त दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसियां ही इन समितियों में परिकल्पित कार्यों को करेंगी। जहां कोई दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी मौजूद न हो, वहां दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी के गठन के लिए मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतिष्ठित बाल कल्याण संगठन या कोई शैक्षिक निकाय दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी के रूप में कार्य कर सकता है। कारा राज्य सरकार से परामर्श करके, दत्तक ग्रहण स्थापन कार्य में न लगे इस प्रकार के संगठन की पहचान कर सकता है। तथापि, दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी के रूप में इसकी मान्यता, यदि अन्य सभी शर्तें पूरी हों, राज्य सरकार के माध्यम से आएगी।

दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी की कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों में एक अध्यक्ष, सचिव तथा कोषाध्यक्ष होगा जिन्हें 3 वर्ष की अवधि के लिए दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी के सदस्यों की साधारण सभा के सदस्यों से और उनके द्वारा चुना जाएगा। कोई भी पदाधिकारी किसी देश से बाहर विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी से नहीं होगा। पदाधिकारी लगातार दो कार्यकाल से अधिक पद पर नहीं रहेगा।

कार्यकारिणी के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष की अवधि के लिए होगा।

कार्यकारिणी समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी :

1. अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष;
2. राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि, जो सहायक निदेशक के पद से कम न हो;
3. संबंधित दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी के क्षेत्राधिकार में कार्यरत जांच एजेंसी/एजेंसियों का एक प्रतिनिधि;
4. अनन्य रूप से भारतीय दत्तक ग्रहण (बिना देश से बाहर दत्तक ग्रहण मान्यता के) में शामिल एजेंसियों का एक प्रतिनिधि;
5. मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसियों (देश से बाहर), जहां कहीं मौजूद हों, का एक प्रतिनिधि;
6. दत्तक माता-पिता संघों, जहां कहीं मौजूद हों, का एक प्रतिनिधि;
7. स्वास्थ्य विभाग, राज्य सरकार से एक प्रतिनिधि; और
8. दत्तक ग्रहण एजेंसियों से किसी सीधे सम्पर्क के बगैर, सामाजिक कार्य/विधि/बाल विकास के क्षेत्र से एक प्रतिनिधि।

उपर्युक्त क्रम सं० 2 से 7 तक के प्रतिनिधि, जहां कहीं ऐसी अधिक एजेंसियां/संगठन हैं, बारी-बारी से होंगे। दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी की कार्यकारिणी समिति में जांच एजेंसी का प्रतिनिधि, दत्तक ग्रहण जांच समिति का सदस्य नहीं होना चाहिए।

8.8 दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी की कार्यकारिणी समिति, दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी के दिन-प्रतिदिन के कृत्य करने के लिए स्टाफ नियुक्त करेगी। वेतन प्राप्त कर्मचारी, कार्यकारिणी समिति के प्रति जवाबदेह होंगे।

8.9 दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी से अनुमति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पहले, कोई भी मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी देश से बाहर दत्तक ग्रहण के लिए विदेशी परिवारों के आवेदनों पर कार्रवाई नहीं करेगी।

8.10 दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी का अनुमति प्रमाणपत्र:

दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी के अनुमति प्रमाणपत्र पर दो अधिकारियों के हस्ताक्षर होंगे। इनमें दत्तक ग्रहण समन्वय समिति के अध्यक्ष और सचिव शामिल हैं। दिशा-निर्देशों के उपाय-2 के पैरा 4.1 के अनुसार, प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

8.11 विद्यमान स्वैच्छिक समन्वय एजेंसियाँ

मौजूदा स्वैच्छिक समन्वय एजेंसियों (वी सी ए) का पुनर्गठन, इन दिशा-निर्देशों के जारी होने के छः माह की अवधि के अन्दर, किया जाएगा और उन्हें दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी कहा जाएगा।

कोई संगठन कारा की वैध मान्यता के बिना, दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी के रूप में कार्य नहीं कर सकता, जैसाकि दिशा-निर्देशों में निर्धारित है।

* * * *

अध्याय - 9

केन्द्रीय प्राधिकरण

9.1 हेग कन्वेंशन का अनुसमर्थन हो जाने के कारण, सभी मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसियों को कारा की मान्यता प्राप्त एजेंसियाँ समझा जाएगा। विदेशी प्रत्याशित दत्तक माता-पिता का आवेदन मूल राज्य के केन्द्रीय प्राधिकरण को प्राप्तकर्ता देश के केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा सीधे या इसके अनुमोदन से इसके किसी मान्यता प्राप्त निकाय के माध्यम से संप्रेषित किया जाएगा।

प्राप्तकर्ता देशों के केन्द्रीय प्राधिकरणों को अपने अनुमोदन-पत्र में रह घोषित करना पड़ेगा कि:

- विदेशी प्रत्याशित दत्तक माता-पिता/अनिवासी भारतीय अपने देश के कानून के अनुसार भारत से बालक को गोद लेने के लिए पात्र और उपयुक्त हैं;

- विदेशी प्रत्याशित दत्तक माता-पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट तथा स्वास्थ्य रिपोर्ट (चिकित्सा व्यावसायिक द्वारा) प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसियों/निकायों के व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा तैयार की जाती हैं;
- विदेशी प्रत्याशित दत्तक माता-पिता, प्रस्तावित दत्तक ग्रहण से सहमत हैं; और
- बालक प्रवेश करने और स्थायी रूप से निवास करने के लिए प्राधिकृत होगा और उसे देश के नैसर्गिक रूप से जन्मे अन्य नागरिक के समतुल्य समझा जाएगा।

9.2 यह एजेंसी प्रत्येक बालक के संदर्भ में बालक के फोटोग्राफों के साथ अनुवर्ती रिपोर्टें उस समय तक जब तक कि दत्तक ग्रहण कार्य पूरा नहीं हो जाता और प्राप्तकर्ता देश में बालक नागरिक नहीं बन जाता, छः माही आधार पर या तो सीधे या अपनी मान्यता प्राप्त एजेंसियों के माध्यम से निम्नलिखित को भेजेगी:

1. कारा; और
2. न्यायालय, जिसने भारत में संरक्षकता प्रदान की।

9.3 किसी विघटन आदि की स्थिति में, यह कन्वेंशन के अनुच्छेद 21 में यथा परिकल्पित समुचित उपाय करेगी जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं :

- कारा को विघटन तथा नए प्रत्याशित दत्तक माता-पिता के साथ बालक के स्थापन की संभावना के बारे में तत्काल सूचित करेगी;
- तथा जहां यह उचित या संभव नहीं हो, कारा को सूचित करते हुए दीर्घावधिक देखरेख का प्रबंध करेगी;
- बालक की भारत में वापसी का प्रबंध करेगी, यदि विघटन के कारण उसके हित में यह अपेक्षित हो।

अध्याय - 10

विविध

10.1 दिशा-निर्देशों का उल्लंघन:

यदि किसी राज्य सरकार या विदेश में भारत के किसी राजनयिक मिशन या कारा या किसी स्रोत के ध्यान में यह बात आती है कि मान्यता प्राप्त भारतीय

स्थापन एजेंसी या सूचीबद्ध विदेशी दत्तक एजेंसी इन दिशा निर्देशों के सभी या किन्हीं प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है या इस तरीके से कार्य कर रही है जो बालकों के हित में नहीं है, कारा अपने विवेक से ऐसी सूचीबद्ध एजेंसी या स्थापन एजेंसी की मान्यता समाप्त कर सकती है या वापस ले सकती है तथा/अथवा कोई अन्य ऐसी कार्रवाई कर सकती है जो आवश्यक समझी जाए ।

- 10.2 ये आशंकाएं व्यक्त की गई हैं कि अनैतिक तत्व शिशुओं का अवैध अंतरण उनके जन्म के समय देश के कुछ अस्पतालों, नर्सिंग होमों, प्रसूति गृहों में दत्तक माता-पिता को करने का इंतजाम कर लेते हैं । उचित मानदंडों और प्रक्रिया का पालन किए बिना, शिशुओं का ऐसा हस्तांतरण अवैध है और इस प्रकार यह बालक के हित में बिल्कुल नहीं है । यदि इस प्रकार की कोई शिकायत कारा के ध्यान में लाई जाती है, वह राज्य सरकार को जांच करवाने और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद समेत केन्द्र और राज्य सरकार के उचित प्राधिकरणों के साथ इस मामले को उठाने की सलाह देगा ।

10.3 छूट योग्य मामले:

देश से बाहर दत्तक ग्रहण संबंधी हेग कन्वेंशन, 1993 के अनुसमर्थन के परिणामस्वरूप दायित्वों और भारतीय बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए, कारा तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार समय-समय पर समुचित उपाय करेंगे । देश से बाहर दत्तक ग्रहण की स्वीकृतियों, मान्यताओं, सभी संबंधित एजेंसियों के सूचीकरण और नवीकरणों के सभी मामलों में, कारा के विवेक से निर्णय लिए जाएंगे और ऐसे मामलों में जहां कारा यह महसूस करे कि किसी विशेष प्रावधान में छूट देने की आवश्यकता है तो वह फाइल में उन कारणों को रिकार्ड करके ऐसा कर सकता है कि किस प्रकार इस तरह की छूट के द्वारा बालक के सर्वोत्तम हित में कार्य किया जा रहा है ।

10.4 दिशा-निर्देशों में संशोधन:

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि वह अपने विवेक से इन दिशा निर्देशों में ऐसे संशोधन, परिवर्धन, लोप या परिवर्तन करे, जैसा वह समय-समय पर आवश्यक समझे ।

* * * *

पर्यायों की शब्दावली

दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी (ए सी ए):

दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी राज्य/क्षेत्र में अपनी सदस्य एजेंसियों के समन्वय के माध्यम से देश में दत्तक ग्रहण को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित, और कारा द्वारा मान्यता प्राप्त तथा देश से बाहर दत्तक ग्रहण में रखे जाने वाले बालक के लिए अनुमति प्रमाणपत्र जारी करने वाली एजेंसी है।

दत्तक ग्रहण जांच एजेंसी (ए एस ए) :

देश में, और देश से बाहर दत्तक ग्रहणों के लिए दत्तक ग्रहण संबंधी आवेदनों की जांच करने हेतु न्यायालय द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र समाज/बाल कल्याण एजेंसी।

केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा):

दत्तक ग्रहणों के मामले में एक केन्द्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाला स्वायत्त निकाय।

केन्द्रीय प्राधिकरण (सी ए):

देश से बाहर दत्तक ग्रहण संबंधी हेग कन्वेंशन, 1993 में यथा परिभाषित।

बाल अध्ययन रिपोर्ट (सी एस आर):

इसमें बालक, इसकी जन्म तिथि, सामाजिक पृष्ठभूमि आदि का ब्यौरा शामिल होगी।

बाल कल्याण समिति (सी डब्ल्यू सी):

देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों से व्यवहार करने वाली समिति, जैसाकि किशोर न्याय अधिनियम, 2000 में परिभाषित है।

अनुमति प्रमाणपत्र (सी सी):

दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र जिसमें देश से बाहर दत्तक ग्रहण में बालक को रखने के लिए मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी को अनुमति दी जाती है। विदेशियों और भारतीय मूल के व्यक्तियों के साथ किए जाने वाले सभी दत्तक ग्रहणों के मामले में अनुमति प्रमाणपत्र अपेक्षित होता है।

सूचीबद्ध विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी (ई एफ ए ए):

देश से बाहर भारतीय बालक के दत्तक ग्रहण के लिए प्रत्याशित विदेशी दत्तक माता-पिता/भारतीय मूल के व्यक्ति आवेदन को प्रायोजित करने हेतु एक विदेशी समाज/बाल कल्याण एजेंसी, जो कारा द्वारा सूचीबद्ध की गई है।

एफ पी ए पी:

विदेशी प्रत्याशित दत्तक माता-पिता।

जी.ए.डब्ल्यू.ए.:

संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890

एच.ए.एम.ए:

हिन्दू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम, 1956

गृह अध्ययन रिपोर्ट (एच एस आर):

इसमें दत्तक परिवार/दम्पति की सामाजिक स्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि, घर का वर्णन, रहन-सहन का स्तर, नातेदारी, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति आदि का ब्यौरा होता है।

देश में दत्तक ग्रहण (आई ए):

भारत में रहने वाले भारतीय माता-पिता द्वारा भारतीय बालक का दत्तक ग्रहण।

देश से बाहर दत्तक ग्रहण (आई सी ए):

प्रत्याशित अनिवासी भारतीय, भारतीय मूल के माता-पिता तथा विदेशी नागरिकों के पास भारतीय बालक का वैध स्थापन ।

किशोर न्याय अधिनियम, 2000:

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000
लाइसेंस प्राप्त दत्तक ग्रहण स्थापन एजेंसी (एल ए पी ए):

देश में दत्तक ग्रहण के लिए राज्य सरकार द्वारा लाइसेंस/मान्यता प्राप्त भारतीय समाज/बाल कल्याण एजेंसी ।

अनापत्ति प्रमाणपत्र (एन ओ सी):

बालक को देश से बाहर दत्तक ग्रहण के लिए प्रत्याशित दत्तक माता-पिता के पास स्थापन किए जाने वाले बालक को अनुमति देने के लिए कारा द्वारा जारी प्रमाण ।

एन आर आई :

अनिवासी भारतीय/(भारतीय पासपोर्ट धारित) ।

शारीरिक जांच रिपोर्ट (पी ई आर):

इसमें बालक की चिकित्सा रिपोर्ट, अस्पताल में रखे जाने की रिपोर्ट, यदि कोई हो, आदि होते हैं ।

पी आई ओ:

भारतीय मूल का व्यक्ति ।

देश से बाहर दत्तक ग्रहण के लिए मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी (आर आई पी ए):

देश से बाहर दत्तक ग्रहण में भारतीय बालकों के स्थापन के लिए कारा द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय समाज/बाल कल्याण एजेंसी ।

संलग्नक - 1केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) के कृत्य

कारा के कृत्य निम्नलिखित होंगे:

1. देश से बाहर दत्तक ग्रहण के संबंध में बालकों के संरक्षण और सहयोग संबंधी हेग कन्वेंशन, 1993 में यथा परिकल्पित दत्तक ग्रहण के मामलों के बारे में केन्द्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना;
2. देश से बाहर दत्तक ग्रहण तथा देश में दत्तक ग्रहण के लिए उपलब्ध बालकों के संबंध में जानकारी के निकासी गृह के रूप में कार्य करना;
3. विदेश में किसी मान्यता प्राप्त समाज या बाल कल्याण एजेंसी के माध्यम से या उस देश में सरकार के स्वामित्व वाले या सरकार द्वारा संचालित किए जाने वाले किसी संगठन के माध्यम से दत्तक ग्रहण में भारतीय बच्चों को लेने के इच्छुक विदेशियों के आवेदनों या अपेक्षित दस्तावेजों के साथ आवेदनों की प्रतियों को प्राप्त करना (जैसाकि श्री लक्ष्मीकांत पाण्डेय बनाम भारत संघ तथा अन्य के मामले में सी आर एल (डब्ल्यू पी) सं० 1171/1982 में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा विहित किया गया है);
4. जब कभी ऐसे आवेदन केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा सीधे प्राप्त किए जाएं, ऐसे आवेदनों को कारा द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय समाज/बाल कल्याण एजेंसियों में से किसी एक को सक्षम न्यायालय में दत्तक ग्रहण के लिए विदेशी माता-पिता के आवेदनों पर कार्रवाई करने हेतु भेजना;
5. मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसियों तथा दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसियों के विनियमन और मानीटरिंग सहित, देश में दत्तक ग्रहण तथा सभी अन्य संबंधित दत्तक ग्रहण मामलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करना;
6. देश से बाहर दत्तक ग्रहण मामलों पर कार्रवाई करने के लिए प्रत्यायित निकायों के रूप में भारतीय स्थापन एजेंसियों को मान्यता देना/नवीकरण करना;

7. भारतीय बालकों को देश से बाहर गोद देने के लिए आवेदनों को प्रायोजित करने हेतु, विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसियों को प्राधिकृत निकायों के रूप में सूचीबद्ध/सूचीबद्धता का नवीकरण करना;
8. भारतीय बच्चों के दत्तक ग्रहण को प्रोत्साहित करने के लिए, दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी (ए सी ए) को मान्यता देना/नवीकरण करना;
9. देश से बाहर दत्तक ग्रहण के मामलों में "अनापत्ति प्रमाणपत्र" जारी करना;
10. ऐसे बालकों के संबंध में एक केन्द्रीय सूचना पूल की स्थापना करने के प्रयोजन के लिए सभी दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसियों से दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी की सहायता के अधीन रखे गए बालकों का विवरण प्राप्त करना । इसके साथ ही, दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसियों के पास पंजीकृत प्रत्याशित दत्तक माता - पिता की संख्या से संबंधित जानकारी भी प्राप्त की जाएगी;
11. मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसियों से उनकी देखरेख में रखे गए बालकों और देश में और देश से बाहर दोनों प्रकार के दत्तक ग्रहण में रखे गए बालकों के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में आवधिक आंकड़े प्राप्त करना । साथ ही, उनके पास पंजीकृत प्रत्याशित दत्तक माता-पिता की संख्या से संबंधित सूचना भी प्राप्त की जाएगी;
12. राज्य सरकारों के माध्यम से या इस उद्देश्य के लिए गठित किसी अन्य एजेंसी या निकाय के माध्यम से मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसियों तथा दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसियों की कार्य प्रणाली का निरीक्षण और मूल्यांकन करना;
13. मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसियों (आर आई पी ए) तथा दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसियों (ए सी ए) से वार्षिक संपरीक्षित लेखा-विवरण मंगाना ।
14. सूचीबद्ध विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसियों से उनके द्वारा किए गए भारतीय बालकों के स्थापन के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक विवरण मंगाना;
15. विदेश ले जाए गए भारतीय बालकों के संबंध में भारतीय राजनयिक मिशनों को वार्षिक आंकड़े भेजना;

16. कारा द्वारा विदेश में सभी सूचीबद्ध विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसियों (ई एफ ए ए) से, उन देशों में जहां ऐसी एजेंसियां स्थित हैं, भारतीय राजनयिक मिशनों के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में दत्तक ग्रहण के उद्देश्य से माता-पिता द्वारा विदेश ले जाए गए बालकों की प्रगति के बारे में आवधिक रिपोर्टें प्राप्त करना और ऐसी रिपोर्टों की जांच करना तथा ऐसी कार्रवाई करना जो आवश्यक समझी जाए;
17. साझा हित के मामलों पर चर्चा करने के लिए दत्तक ग्रहण के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक समन्वय एजेंसियों की आवधिक बैठकें आयोजित करना एवं उनकी व्यवस्था करना;
18. प्रचार और जागरूकता कार्यक्रमों के द्वारा सामुदायिक सहयोग के माध्यम से बालकों की प्रायोजकता की व्यवस्था करना;
19. देश में स्वयं ही बच्चों के दत्तक ग्रहण को प्रोत्साहित करने में सामुदायिक राय और सामुदायिक संसाधनों को जुटाना तथा देश में बालकों का दत्तक ग्रहण और सामान्य रूप से बाल कल्याण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सभी अन्य उपाय करना;
20. सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा बाल कल्याण संबंधी कार्य में विशेष रूप से दत्तक ग्रहण के द्वारा बालकों के पुनर्वास कार्य में लगे अन्य व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना तथा स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा संचालित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को मानकीकृत करना;
21. न्यायालयों को स्थापन एजेंसियों और जांच एजेंसियों समेत अनेक स्रोतों से उन्हें भेजी गई सूचना की क्रास जांच करने या पुनः सत्यापित करने में मदद करना या बच्चों के दत्तक ग्रहण संबंधी मामलों में स्वतंत्र राय देना;
22. परिवार के अधिकार के रूप में बालक के दत्तक ग्रहण से संबंधित किसी अन्य कार्यकलाप के संबंध में कार्रवाई करना;
23. जहां कहीं आवश्यक हों, 'विदेशी केन्द्रीय प्राधिकरणों के साथ हेग कन्वेंशन के तहत यथा निर्धारित द्विपक्षीय करार निष्पादित करना;
24. देश से बाहर दत्तक ग्रहण में रखे गए बालक से संबंधित विघटन की स्थिति में संबंधित केन्द्रीय प्राधिकरण/अन्य उचित प्राधिकरण, सूचीबद्ध एजेंसी तथा मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी से सम्पर्क करना और बालक के सर्वोत्तम हित में कार्रवाई करना; और

25. देश से बार दत्तक ग्रहण में किसी अनैतिक कार्य की सूचना मिलने पर या वर्तमान दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर, किसी मान्यता प्राप्त/सूचीबद्ध एजेंसी के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करना तथा आगे सक्षम प्राधिकरण से जांच/छानबीन करवाना और ऐसे चूककर्ता व्यक्ति/एजेंसियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करना ।

संलग्नक-2

सूचीबद्ध विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी से अपेक्षित दस्तावेजों की सूची

भारतीय बालक के देश से बाहर दत्तक ग्रहण संबंधी आवेदन पर विचार करने के लिए विदेशी दत्तक माता-पिता तथा भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध संमाज या कल्याण एजेंसी से अपेक्षित दस्तावेजों की सूची :

- (क) सूचीबद्ध विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी/केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति/सरकारी विभागों के व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा तैयार की गई विदेशी दत्तक माता-पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट । *
- (ख) दत्तक माता-पिता/परिवार के हाल ही में खींचे गए फोटोग्राफ ।
- (ग) प्रत्याशित दत्तक माता-पिता का विवाह-प्रमाणपत्र ।
- (घ) किसी मेडिकल डाक्टर द्वारा विधिवत प्रमाणित दत्तक माता-पिता का आरोग्यता संबंधी प्रमाणपत्र ।
- (ङ) सहायक दस्तावेजों, नियोक्ता का प्रमाणपत्र/आयकर विवरणी आदेश तथा बैंक रेफरेंसेज समेत प्रत्याशित दत्तक माता-पिता की वित्तीय स्थिति से संबंधित घोषणा ।
- (च) दत्तक ग्रहण के लिए पीएपी की उपयुक्तता के बारे में परिचित व्यक्ति/संबंधियों द्वारा तीन संदर्भ पत्र ।
- (छ) पहले गोद लिए गए बालक/बालकों, यदि कोई हो, की दत्तक ग्रहण डिक्री ।
- (ज) पुलिस अनुमति रिपोर्ट ।
- (झ) आयु के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाणपत्र/पासपोर्ट ।
- (ञ) केन्द्रीय प्राधिकरण का अनुमोदन (उपयुक्तता रिपोर्ट-गृह अध्ययन रिपोर्ट) ।
- (ट) विदेशी प्रत्याशित दत्तक माता-पिता की नागरिकता/राष्ट्रीयता का दस्तावेजी प्रमाण ।

* गृह अध्ययन रिपोर्ट में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए : (क) सामाजिक स्थिति तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि; (ख) घर का वर्णन; (ग) रहन-सहन का स्तर जैसा कि यह घर में दिखाई देता है; (घ) पति और पत्नी के वर्तमान संबंध; (ङ) माता-पिता और बच्चों के वर्तमान संबंध (यदि कोई बालक हो); (च) पहले से गोद लिए गए बच्चों में विकास (यदि कोई हों); (छ) दम्पति और एक-दूसरे के परिवारों के बीच संबंध; (ज) दम्पति की रोजगार स्थिति; (झ) स्वास्थ्य का व्यौरा जैसे क्लिनिकल जांच, श्रवण स्थिति, विगत की बीमारी, आदि (चिकित्सा प्रमाणपत्र आदि); (ञ) दम्पति की आर्थिक स्थिति; (ट) बालक के लिए आवास स्थान; (ठ) स्कूल की सुविधाएं; (ड) घर में सुविधाएं; (ढ) भारतीय बालक को गोद लेने की इच्छा के कारण; (ण) दत्तक ग्रहण के प्रति दादा-दादी तथा नातेदारों का रुझान; (त) दत्तक बालक के लिए प्रत्याशित योजनाएं; तथा (थ) प्रत्याशित दत्तक माता-पिता की कानूनी स्थिति ।

- (ठ) विदेशी को प्रायोजित करने वाले सूचीबद्ध विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी से इस आशय का वचनबंध कि विदेशी दत्तक माता-पिता द्वारा बालक को देश के कानून के अनुसार बालक के आगमन के समय से अधिक से अधिक दो वर्ष की अवधि के भीतर कानूनी रूप से गोद ले लिया जाएगा और ज्यों ही दत्तक ग्रहण प्रभावी हो जाएगा, सूचीबद्ध एजेंसी प्रत्येक दत्तक आदेश की प्रमाणित प्रतियां सभी संबंधितों को भेजेगी ।
- (ड) सूचीबद्ध विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी से यह वचनबंध कि बालक से संबंधित अनुवर्ती रिपोर्ट, उसके अद्यतन फोटोग्राफ के साथ छःमाही आधार पर 2 वर्ष की अवधि के लिए या ऐसी अवधि तक भेजी जाएगी, जब तक कानूनी दत्तक ग्रहण पूर्ण न हो जाए और प्राप्तकर्ता देश में बालक को नागरिकता प्राप्त नहीं हो जाती ।
- (ढ) भारत में मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी के कार्यालय/अधिकारी के पक्ष में प्रत्याशित दत्तक माता-पिता से पावर ऑफ एटर्नी जिसके मामले पर कार्रवाई करने में आवश्यकता होगी और ऐसी पावर ऑफ एटर्नी द्वारा, यदि विदेशी भारत में आने की स्थिति में नहीं हो, तो उस विदेशी की ओर से एटर्नी के मामलों के निपटान के लिए प्राधिकृत किया जाना चाहिए ।
- (ण) सूचीबद्ध विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी से इस आशय का वचनबंध कि वैध दत्तक ग्रहण प्रभावी होने से पहले विदेशी के परिवार के विघटन की स्थिति में, वह बालक की देखरेख करेगी और केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के अनुमोदन से बालक के लिए उचित वैकल्पिक स्थापन ढूंढेगी । कारा से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लेने के बाद, यह संबंधित मान्यताप्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी की सहायता से संरक्षकता संबंधी कार्यवाहियां करने वाले संबंधित भारतीय न्यायालय को वैकल्पिक स्थापन की सूचना देगी और ऐसी जानकारी, पैरा 6.7 (ख) के अनुसार, सभी संबंधितों की दी जाएगी ।
- (त) सूचीबद्ध विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी से यह वचनबंध कि वह दिशा-निर्देशों के पैरा 5.17 के अनुसार, मान्यताप्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी को दत्तक ग्रहण फीस का भुगतान करेगी ।

- (थ) विदेशी के आवेदन को प्रायोजित करने वाली सूचीबद्ध विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी से इस आशय का वचनबंध कि दत्तक माता-पिता को अपने देश के कानून के अनुसार बालक को गोद लेने की अनुमति है तथा बालक को प्रवेश परमिट/वीजा मिलेगा ।

संलग्नक-3

दस्तावेजों की सूची

मान्यताप्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए कारा के समक्ष प्रस्तुत करना है

- (क) मान्यताप्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी को कारा द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना चाहिए ।
- (ख) संलग्नक-2 में सूचीबद्ध सभी दस्तावेज ।
- (ग) प्रत्याशित दत्तक माता-पिता द्वारा विधिवत स्वीकार और अनुमोदित की गई "बाल अध्ययन रिपोर्ट" (पैरा 4.1 उपाय-1 के अनुसार नोटाराइज/सत्यापित की गई) ।
- (घ) प्रत्याशित दत्तक माता-पिता द्वारा विधिवत स्वीकार और अनुमोदित की गई बालक की शारीरिक जांच रिपोर्ट (पैरा 4.1 उपाय-1 के अनुसार नोटाराइज/सत्यापित की गई) ।
- (ङ) यह प्रमाण कि बालक कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण के लिए मुक्त है (बाल कल्याण समिति का प्रमाणपत्र/अभ्यर्पण विलेख की प्रति) ।
- (च) दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी का अनुमति प्रमाणपत्र (अनिवासी भारतीय के लिए अपेक्षित नहीं) ।

संलग्नक-4

अनन्तिम समय अनुसूची
देश से बाहर दत्तक ग्रहण में बालकों के स्थापन के लिए

क्रम सं०	संबंधित एजेंसी/प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली सेवाएं	प्रस्तावित समय सीमा
1.	मान्यताप्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी द्वारा बालक को घरेलू दत्तक ग्रहण में रखना	बालक के दत्तक ग्रहण के लिए कानूनी रूप से मुक्त हो जाने की तारीख से 30 दिन के अंदर
2.	दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी द्वारा अनुमति प्रमाणपत्र जारी करना	सामान्य बालक की स्थिति में 31वें दिन को और विशेष जरूरतों वाले बालक की स्थिति में 10 दिन के अंदर ।
3.	देश से बाहर दत्तक ग्रहण के लिए कारा द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करना	मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी से सभी तरह से पूर्ण भरे हुए अनापत्ति प्रमाणपत्र आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के अंदर ।
4.	कारा के अनापत्ति प्रमाणपत्र के बाद, मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी द्वारा मामला उचित कार्रवाई के लिए सक्षम न्यायालय में दाखिल करना	कारा से अनापत्ति प्रमाणपत्र की तारीख से 15 दिन के अंदर ।
5.	सक्षम न्यायालय द्वारा मामले को निपटाना	मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी द्वारा सब प्रकार से पूर्ण भरे हुए आवेदन देने की तारीख से दो माह के अंदर ।
6.	संबंधित पासपोर्ट कार्यालय द्वारा बालक के लिए पासपोर्ट जारी करना ।	प्रस्तुत करने की तारीख से 10 दिन के भीतर ।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
RESOLUTION

New Delhi, the 14th February, 2006

No. 4-1/2003-CARA.—In order to facilitate the implementation of the norms, principles and procedures relating to the adoption of children, the Government of India had issued the Revised Guidelines for Adoption of Indian Children in 1995 vide notification dated 29.5.1995.

In view of the developments that have taken place thereafter, the Guidelines have been further revised. The Guidelines for Adoption from India – 2006 which will replace the earlier Guidelines are for the information and adherence of general public, voluntary agencies and other concerned with the subject matter.

P. NARAYANA MURTHY, Jt. Secy.

GUIDELINES FOR ADOPTION FROM INDIA—2006

CHAPTER-I

INTRODUCTION

1.1 Aims and Objects

The objective of the Guidelines is to provide a sound basis for inter-country adoption within the framework of the norms and principles laid down by the Honourable Supreme Court of India in the series of Judgments delivered in L.K. Pandey vs. Union of India and Others between 1984 and 1991 and various other court orders from time to time and to take all other measures necessary for the promotion of in-country adoption of children as well as welfare of children in general.

1.2 The goal is to find a family for as many orphan children as possible and to safeguard their interests as visualized in the UN Convention on Child Rights and Hague Convention on Inter-country Adoption (both ratified by India).

1.3 The Government of India, in pursuance of its constitutional mandate, has evolved a National Policy for the welfare of children. The thrust of this policy is summed up in the following words:

“The Nation's children are a supremely important asset. Their nurture and solicitude are our responsibility. Children's programmes should find a prominent part in our national plans for the development of human resources, so that our children grow up to become robust citizens, physically fit,

mentally alert and morally healthy, endowed with the skills and motivation needed by society. Equal opportunities for development to all children during the period of growth should be our aim, for this would serve our larger purpose of reducing inequality and ensuring social justice."

1.4 The National Policy for the Welfare of Children also stresses the vital role which the voluntary organisations have to play in the field of education, health, recreation and social welfare services for children and declares that it shall be the endeavor of the state to encourage and strengthen such voluntary organisations.

1.5 India has signed the Hague Convention on Inter-country Adoption-1993 on 9 January, 2003 and ratified the same on 6 June, 2003 with a view to strengthening International Cooperation and Protection of Indian Children placed in Inter-country adoption. For the purpose of implementation of the Convention in our country, Ministry of Social Justice & Empowerment is functioning as the Administrative Ministry and Central Adoption Resource Authority (CARA) as the Central Authority.

1.6 Need of Family Support for the Development of Children

It is the responsibility of the community and of the state to provide both institutional and non-institutional support to orphans and destitute children. The Government of India considers adoption as the best non-institutional support for rehabilitation of such children because only a family environment can provide them the best opportunity to fulfill their potential.

1.7 Review of Adoption Procedure

The "Revised Guidelines for the Adoption of Indian Children-1995" were issued by the Govt. of India on 21st May'1995 and it has now been decided to further revise this Guidelines keeping in view the developments such as the ratification of the Hague Convention on Inter-country Adoption-1993 by India on 06.06.2003 etc. since then.

Before finalization of the Guidelines, suggestions and opinions were sought from the State Governments/UTs., Recognised Indian Placement Agencies, Adoption Coordinating Agencies and Adoption Scrutinizing Agencies.

The "Guidelines for Inter-country Adoption of Indian Children-2005" will supersede all previous Guidelines issued in this regard by the Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India, New Delhi.

CHAPTER-II

AUTHORITIES & AGENCIES

2.1 Government of India

In the Government of India all policy matters relating to adoption are dealt with by the Ministry of Social Justice & Empowerment. Under the aegis of the Ministry, the Central Adoption Resource Authority (hereinafter called CARA) functions as a nodal body and the Central Authority for adoption matters. It is a body registered under the Societies Registration Act, 1860 on 18th March, 1999 with its headquarter in New Delhi. The functions of CARA are listed at Annexure-1.

2.2 Central Authorities

Government departments or any other duly authorised body notified by their Govt. to function as Central Authorities of foreign countries under the Hague Convention on Inter-country Adoption-1993 will be treated as Central Authorities by CARA.

2.3 Foreign Adoption Agencies enlisted by CARA shall be called Enlisted Foreign Adoption Agencies (EFAAs)

CARA will approve/authorize and maintain a list of all Enlisted Foreign Adoption Agencies (EFAAs) who can forward applications of foreign prospective adoptive parents including NRIs (Non Resident Indians) to it for approval.

2.4 Recognized Indian Agencies for Inter-country Adoption (RIPA)

CARA will recognize/accredit Indian Placement Agencies for Inter-country Adoption (RIPA). It shall publish once a year a list of RIPAs in leading national and vernaculars newspapers. CARA shall send this list once a year to the High Courts in the country for circulation to the District Courts. RIPAs shall function as accredited bodies as per the Hague Convention of 1993.

2.5 Adoption Coordinating Agencies (ACAs)

There shall be a centralized agency namely Adoption Coordinating Agency (ACA) earlier known as Voluntary Coordinating Agency (VCA) in the state or even in a large city where there are several recognised placement and child welfare agencies to promote in-country adoption and issue clearance in case of all Inter-country adoptions.

2.6 **Adoption Scrutiny Agencies (ASAs)**

It is open to the Court to seek assistance from the Indian Council for Child Welfare or the Indian Council for Social Welfare or any of its branches/any independent, reputed and officially recognized Child/Social Welfare Agency for scrutinizing the adoption applications with a view to ensure the welfare of the child.

2.7 **Indian Diplomatic Missions**

Indian Diplomatic Missions abroad, will liaison with concerned Central/Public Authorities to ensure safeguards of children of Indian origin adopted by foreign parents against neglect, maltreatment, exploitation or abuse. They will receive a statement of all Indian children cleared for adoption by foreign nationals (including NRIs/PIOs) from CARA once a year.

Indian Missions will be encouraged to interact with the Foreign Enlisted Agencies and Central Authorities in their area of jurisdiction and arrange get togethers of the adopted children and their parents.

2.8 CARA may levy any recognition/renewal processing fee or any other charges with the approval of the Ministry of Social Justice & Empowerment from time to time.

CHAPTER-III

ROLE OF STATE GOVERNMENTS/UNION TERRITORIES

3.1 **Licensing of Children's Homes**

The State Governments (the term "State Government" to include Union Territory Administration wherever applicable) will license/recognise all such children's homes engaged in adoption programmes of destitute, abandoned or orphaned children under the relevant Act/statute/rules or order as operative in the state or UT.

3.2 The State Governments will licence/recognise Indian adoption agencies for in-country adoption as per the procedure laid down in Guidelines for In-country Adoptions 2004 and shall forward applications of Indian agencies seeking recognition for inter-country adoption to the Central Adoption Resource Authority after proper verification. State Governments should not recommend either new recognition or renewals if they have not permitted the concerned agency to undertake in-country adoption. All agencies will also have to be licenced/registered under the relevant Act of the State to qualify for recognition.

3.3 List of Adoption Agencies

From among the above Homes, the State Government will separately maintain a list of all such Homes or Agencies handling in-country and inter-country adoptions and will maintain a list of all children who are declared legally free for adoption by the competent authorities in these institutions.

3.4 Role and Functions of State Governments:

- (i) Monitor the adoption programme and the activities of all adoption agencies, RIPAs & ACAs within its jurisdiction.
- (ii) Encourage and promote placement of such children in adoption or guardianship with families within the country.
- (iii) If there is no ACA in particular state, until the ACA is set-up, the Department of the concerned State Govt. may function as ACA.
- (iv) Enforce the Orphanages and Other Charitable Homes (Supervision and Control) Act, 1960 and/or Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000 and/or formulate suitable alternate rules in order to maintain certain minimum standards for child care in child welfare institutions. Homes not licensed/recognised by the State Governments will not be allowed to carry out the function of adoption.
- (v) Receive all applications from adoption agencies for fresh recognition as well as renewal of recognition for inter-country adoption. After due verification it will give its clear recommendation alongwith Inspection Report or otherwise with supporting documents to CARA.
- (vi) Form an Advisory Committee on adoption which shall have the following as members:

(a)	Secretary, Women & Child Development Deptt. /Social Welfare/ Panchayat Raj.	1	Chairman.
(b)	Director, Welfare/Social Welfare/ Women & Child Development.	1	Member
(c)	Two representatives of adoption placement agencies.	2	Member
(d)	One representative of ACA/s	1	Member
(e)	One representative of Adoption Scrutinising Agencies.	1	Member
(f)	Three experts in the field of Social and Child Welfare.	3	Member

The Committee will meet periodically to discuss child welfare measures, specifically ways and means to promote in-country adoption of children and

take all such decisions pertaining to policy issues on adoption. The tenure of such a committee shall be three years.

- (vii) The State Government should also set up an Adoption Cell in the Directorate of Social Welfare to co-ordinate, monitor and develop the work of adoption and render all assistance to the Advisory Committee on Adoption. The Adoption Cell should consist of at least one officer and assistant or more based on the number of agencies licensed and recognized in the State.
- (viii) Ensure that the provisions of the Supreme Court judgement, the State JJ Rules based on JJ Act, 2000 and the Guidelines for Incountry Adoption-2004, are adhered to.
- (ix) State Governments shall receive data on new arrivals and death of the children from the adoption agencies and shall furnish annual data on adoption to CARA.
- (x) State Governments may direct all the CWCs/JJBs working in the States to submit periodical data to ACA and Adoption Cell relating to adoption matters.

3.5 Inspection of Adoption Agencies:

CARA/State Government will periodically and at least once a year, inspect all Licensed and Recognised Adoption Placement Agencies as also their papers, documents and activities connected with the service for children, in order to verify the following:-

- (i) That adoption as an activity is being pursued by the organization as a welfare measure in the interest of children and not as a commercial activity.
- (ii) That proper records are being maintained for children admitted to the homes.
- (iii) That the children admitted are provided with quality child care and basic minimum facilities for their care, education and development in the institution or Foster Homes.
- (iv) That lists of persons interested in adopting a child or taking a child under guardianship are being maintained by the organisation regularly.
- (v) That the accounts of the organisation are being maintained and audited annually without delay and that the auditor's reports confirm that the accounts are fair and accurate; that any organisation which is in receipt of foreign funding is duly registered with the Ministry of Home Affairs and has otherwise complied with the provisions of the Foreign Contributions (Regulation) Act, 1976.

- (vi) That the organisation is receiving regular progress reports about the well-being of children given in adoption.
- (vii) That qualified staff having social work experience are employed by the agency/organisation to supervise the care of children or they have access to such staff.
- (viii) That in the case of children placed in pre-Adoption care/foster care with prospective adoptive parents, the cases have been legalized.
- (ix) A separate register is kept for children given in pre-adoption foster care in all cases.
- (x) That a Central Register of prospective adoptive parents is maintained.

3.6 **Monitoring of Performance**

The State Government shall call for information and data every quarter from all RIPAs and Licensed Adoption Placement Agencies (LAPAs) engaged in adoption in order to monitor the functioning of these agencies. The data shall be called for in a proforma to be prescribed by the Central Adoption Resource Authority. An annual report and audited statement of accounts shall be received from all Adoption Agencies.

- 3.7 The State Government shall take all such measures as are deemed necessary to actively encourage in-country adoption of children in preference to inter-country adoption. Special care/efforts shall be made for rehabilitation of children in institutions through placement by adoption.

- 3.8 The State Government may take appropriate legal action against persons and institutions including Nursing Homes and Hospitals involved in illegal adoption work.

3.9 **Suspension/termination of recognition of RIPA**

In case of a report of violation of guidelines by a Recognised Indian Placement Agency, the State Government shall inform CARA for taking appropriate action. In case of suspension/withdrawal of recognition by CARA, suitable alternative rehabilitation plans have to be ensured by the State Government for children awaiting adoption through other Recognised Indian Placement Agencies.

CHAPTER-IV

PROCEDURE FOR INTER-COUNTRY ADOPTION

The Supreme Court of India has laid down that every application from a foreigner/NRI/PIO (as applicable) desiring to adopt a child must be sponsored by a social or child welfare agency recognised or licensed by the Government or a Department of the Foreign Govt. to sponsor such cases in the country in which the foreigner is resident. The foreign agency should also be an agency 'authorised' by CARA, Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India. No application by a foreigner/NRI/PIO for taking a child in adoption should be entertained directly by any social or child welfare agency in India.

4.1 Criteria for Foreign Prospective Adoptive Parent/s (FPAP):

- Married couple with 5 years of a stable relationship, age, financial and health status with reasonable income to support the child should be evident in the Home Study Report.
- Prospective adoptive parents having composite age of 90 years or less can adopt infants and young children. These provisions may be suitably relaxed in exceptional cases, such as older children and children with special needs, for reasons clearly stated in the Home Study Report. However, in no case should the age of any one of the prospective adoptive parents exceed 55 years.
- Single persons (never married, widowed, divorced) up to 45 years can also adopt.
- Age difference of the adoptive parents and child should be 21 years or more.
- A FPAP in no case should be less than 30 years and more than 55 years.
- A second adoption from India will be considered only when the legal adoption of the first child is completed.
- Same sex couples are not eligible to adopt.

The following procedures will be followed in all cases of inter-country adoptions:

Step I) Enlisted Foreign Adoption Agency (EFAA)

- The applicants will have to contact or register with an Enlisted Foreign Adoption Agency (EFAA)/Central Authority/Govt. Deptt. in their country, in which they are resident, which will prepare the

Home Study Report (HSR) etc. The validity of "Home Study Report" will be for a period of two years. HSR report prepared before two years will be updated at referral.

- The applicants should obtain the permission of the competent authority for adopting a child from India. Where such Central Authorities or Government departments are not available, then the applications may be sent by the enlisted agency with requisite documents including documentary proof that the applicant is permitted to adopt from India
- The adoption application dossier should contain all documents prescribed in Annexure-2. All documents are to be notarized. The signature of the notary is either to be attested by the Indian Embassy/High Commission or the appropriate Govt. Department of the receiving country. If the documents are in any language other than English, then the originals must be accompanied by attested translations
- A copy of the application of the prospective adoptive parents along with the copies of the HSR and other documents will have to be forwarded to RIPA by the Enlisted Foreign Adoption Agency (EFAA) or Central Authority of that country.

Step II) Role of Recognised Indian Placement Agency (RIPA)

- On receipt of the documents, the Indian Agency will make efforts to match a child who is legally free for inter-country adoption with the applicant.
- In case no suitable match is possible within 3 months, the RIPA will inform the EFAA and CARA with the reasons therefore.

Step III) Child being declared free for inter-country adoption - Clearance by ACA

- Before a RIPA proposes to place a child in the Inter country adoption, it must apply to the ACA for assistance for Indian placement.
- The child should be legally free for adoption. ACA will find a suitable Indian prospective adoptive parent within 30 days, failing which it will issue clearance certificate for inter-country adoption.
- ACA will issue clearance for inter-country adoption within 10 days in case of older children above 6 years, siblings or twins and Special Needs Children as per the additional guidelines issued in this regard.

- In case the ACA cannot find suitable Indian parent/parents within 30 days, it will be incumbent upon the ACA to issue a Clearance Certificate on the 31st day.
- If ACA Clearance is not given on 31st day, the clearance of ACA will be assumed unless ACA has sought clarification within the stipulation period of 30 days.
- NRI parent(s) (at least one parent) HOLDING Indian Passport will be exempted ACA Clearance, but they have to follow all other procedures as per the Guidelines.

Step IV) Matching of the Child Study Report with Home Study Report of FPAP by RIPA

- After a successful matching, the RIPA will forward the complete dossier as per Annexure 3 to CARA for issuance of "No Objection Certificate".

Step V) Issue of No Objection Certificate (NOC) by CARA

- RIPA shall make application for CARA NOC in case of foreign/PIO parents only after ACA Clearance Certificate is obtained.
- CARA will issue the 'NOC' within 15 days from the date of receipt of the adoption dossier if complete in all respect.
- If any query or clarification is sought by CARA, it will be replied to by the RIPA within 10 days.
- No Indian Placement Agency can file an application in the competent court for inter-country adoption without a "No Objection Certificate" from CARA.

Step VI) Filing of Petition in the Court

- On receipt of the NOC from CARA, the RIPA shall file a petition for adoption/guardianship in the competent court within 15 days.
- The competent court may issue an appropriate order for the placement of the child with FPAP.
- As per the Hon'ble Supreme Court directions, the concerned Court may dispose the case within 2 months.

Step VII) Passport and Visa

- RIPA has to apply in the Regional Passport Office for obtaining an Indian Passport in favour of the child.
- The concerned Regional Passport Officer may issue the Passport within 10 days.

- Thereafter the VISA entry permit may be issued by the Consulate/Embassy/High Commission of the concerned country for the child.

Step VIII) Child travels to adoptive country

- The adoptive parent/parents will have to come to India and accompany the child back to their country.

4.2 Criteria for eligible children:

- The child must be legally free for adoption.
- Clearance from ACA/State Government is mandatory for all children except wherever exempted under the Guidelines.
- Siblings/twins/triplets cannot be separated except in exceptional cases.
- Two unrelated children cannot be proposed to a foreign family at a time.
- A child may as far as possible be placed in adoption before it reaches the age of 12.
- The consent of the child has to be obtained wherever applicable.

4.3 Where there is no Enlisted Foreign Adoption Agency (EFAA)

In the case of an Indian National residing in a country where there is no Enlisted Agency, CARA may allow an organisation or individual recommended by the Indian Embassy to do the Home Study Report (HSR), undertaking as prescribed in the Guidelines and other documentation. The said application may be forwarded with the approval of the Indian Embassy to CARA.

Wherever there is no Foreign Adoption Agency enlisted by CARA in any country, the concerned Government Department/Ministry or any authorized body of that country may forward the original application and related documents of the prospective adoptive parents to CARA through the Indian Embassy/High Commission. In case of resident non-citizens where the host Govt. may not be willing to sponsor the cases, the documentation may be done through the Embassy of the country to which the applicant belongs. Home studies however will have to be prepared by a qualified Agency/Social Worker in all cases. In case CARA receives the papers it will send those papers to any of the Recognised Indian Placement Agencies (RIPA) for further processing the case only after HSR has been approved by it. The procedure to be adopted thereafter shall be the same as indicated in the process.

4.4 Foreign nationals living in India

In case of foreigners who have been living in India for one year or more, the HSR and other connected documents may be prepared by the RIPA which is processing the application of such foreigners for the guardianship of the child. An undertaking should be given by the concerned Embassy/High Commission that the child will be legally adopted in that country and also mention an agency/orgn. who would send the progress reports and take care of the child in case of any disruption as and when the child is taken abroad. However a certificate is required from the competent authority in the country of permanent residence of the FPAP indicating that the child shall be allowed to enter the country and get adopted in due course.

4.5 Rights of the child taken abroad

When the Court makes an order appointing adoptive parents as the guardians of the child, the order shall contain an undertaking of the adoptive parents that they shall protect and safeguard the best interest of the child and that the child would be legally adopted in the receiving State not later than two years from the date of the order. On such adoption in the receiving State, subject to the Laws of the country the child would have all rights recognized under International Law.

CHAPTER-V

RECOGNISED INDIAN PLACEMENT AGENCIES (RIPA)

5.1 Only such voluntary agencies/institutions as are primarily engaged in child welfare programmes for the growth and development of children can undertake processing of adoption cases as a part of their total activities and may apply for recognition for inter-country adoption to CARA through the State Government. Only Recognised Agencies can undertake Inter-country Adoption. RIPAs will be known as accredited bodies for the purpose of processing inter-country adoption applications

5.2 Listing with Authorities

Every institution and child welfare agency engaged in care and custody of children or in adoption work or any other activity related to orphaned, abandoned, destitute, neglected or relinquished children shall immediately be listed by the concerned State Government and such list shall be forwarded to CARA.

5.3 Criteria for Recognition of Indian Placement Agency (RIPA)

No agency will engage in placement of inter-country adoption unless it is licensed by the State Government and recognised by CARA. Any Indian agency desirous of undertaking inter-country adoption work shall apply for recognition to the Central Adoption Resource Authority, through the State Government concerned and only such agencies are recognised by the Central Adoption Resource Authority, shall be entitled to undertake processing of inter-country adoption work. Such agencies shall be termed "Recognized Indian Placement Agencies". The General criteria for granting recognition should be as follows:

- (a) It is a society registered under the Societies Registration Act, 1860 or a Trust created under the Charitable Trusts Act, or an organisation registered under an appropriate law which has worked for the welfare of Women and Children during the preceding five years;
- (b) Only such voluntary agencies primarily engaged in child welfare programmes which undertake adoption as a part of their total activities may apply for recognition for inter-country adoption to the Central Adoption Resource Authority.
- (c) The organisation should be duly licensed/recognised by the State Government under the Orphanages and Other Charitable Homes (Supervision and Control) Act, 1960 and/or Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000 and/or any alternate rules or order to maintain certain minimum standards for child care in child welfare institutions. The organisation should have been functioning for a period of three years in the field of in-country adoption at the time of applying for Inter-country recognition. This will be relaxable, for organisations working in the North East region and J & K, in meritorious cases.
- (d) The organization should also have a certificate of recognition from concerned State Govt. for doing in country adoption in accordance with section 41(4) of the JJ Act 2000 and corresponding states JJ Rules.
- (e) Where the adoption programme is part of a larger organisation there should be a sub-committee to run the adoption programme and closely monitor the same. This Committee shall have at least some professional members with experience in the field of Child Development/Social Welfare/Law.
- (f) It should have appropriate residential institution/Home for the protection and care of children including infants.
- (g) It should run on a non-commercial and non-profit basis.

- (h) The Chief Executive of the organisation should be willing to sign a written undertaking to follow the Guidelines laid down by the Supreme Court of India, those prescribed by the Government of India and the conditions imposed, if any, by CARA at the time of Recognition and Renewal.
- (i) Recognition of the agency should be recommended by the State Government concerned.
- (j) It should have required professional staff to run the adoption agency.

Recognition to an Indian agency shall be granted normally for a period of 3 years, subject to the conditions laid down in these Guidelines. The decision of CARA shall be final in this regard.

5.4 List of Prospective Adoptive Parents

Every Recognized/Licensed Indian Placement Agency shall regularly maintain a list of all registered prospective Indian adoptive parents containing their names, addresses and other relevant data. NRIs holding Indian passports can be registered with the Agencies.

5.5 Steps to be followed by RIPA

Step 1) Intake of Children

- All names of children admitted, including surrendered children, to a Recognised Indian Placement Agency should be entered in the admission register with all the available information in the format prescribed by the CARA. A list of all children and newly arrived children should be sent to the ACA/Adoption Cell of the State Govt. or other Competent Authority on monthly basis. In case of the death of any child in the Agency, the same has to be immediately intimated to the State Govt./Concerned Authority.
- Every recognized/licensed Indian Placement Agency will maintain a separate file for each child with the child's complete case history. Further, the specific details of surrender, the belongings of the child left by the biological mother and other required information related to the child should be maintained/prescribed/documented. No Agency will be allowed to process cases of children belonging to other agencies including non-recognised agencies unless the concerned child has been transferred legally and physically to its custody for a minimum period of one month.
- On admission of a child in the agency, the latter has to inform the CWC/local authority within 24 hours.

Step 2) Child becoming legally free for adoption

- When RIPA receives a child, its first responsibility is to trace the biological parents and restore the child. The biological parent/parents should be counselled and duly informed by the agency concerned of the effect of their consent for adoption and the alternatives available for the care and maintenance of the child. No Agency will directly or through agents, attempt to induce biological parents with monetary and other incentives to surrender their children.

Step 3) Priority to In-country Adoption

- All the adoption agencies will give priority to In-country adoptions so that every child gets an opportunity to find a family within its own cultural milieu. RIPA should exhaust all possibilities to place a child within the country within a period of 30 days.
- Each Recognized Indian Placement Agency is required to adhere to the following order of priority while considering the adoption of Indian children:
 1. Indian citizens living in India.
 2. Indian citizens living abroad.
 3. Both Parents of Indian origin abroad.* (PIO)
 4. One parent of Indian origin abroad.* (PIO)
 5. Foreign families.

(Definition of NRI and PIO for the purpose is given at **)

Step 4) Documentation of efforts

- Every Recognized Indian Placement Agency shall give full details of the child to the prospective adoptive parents (except the names and addresses of the biological parents), where known to the agency. Every Recognised Indian Placement Agency will keep a complete record in chronological order of the efforts made for locating Indian parents. The reasons for non-placement of a child in in-country adoption should be recorded. The names, address & contact numbers of Indian families who have not accepted the child should be made available to CARA, ACA and the State Government whenever required.
- When all efforts to place the child with Indian parents fail as per priority one, then the procedure as laid down in Chapter IV will be followed.

**NRI means Indian citizens who hold Indian passports and are presently residing abroad.

Persons of Indian origin (PIO) means a foreign citizen (not being a citizen of Pakistan, Bangladesh and other countries as may be specified by the Central Govt. from time to time) if:

- (a) he/she at any time held an Indian Passport; or
- (b) he/she or either of his parents or grand parents or great grand parents was born in and permanently resident in India as defined in the govt. of India Act 1935 and other territories that became part of India thereafter provided neither was at any time a citizen of any of the aforesaid countries (as referred to) above;
- (c) he or she is a spouse of a citizen of India or a person of Indian origin covered under (a) or (b) above.

5.6 Quarterly Data to be furnished to Authorities

Every Recognised Indian Adoption Placement Agency will furnish quarterly data to the State Government in which the agency is operating and a quarterly statement to the Central Adoption Resource Authority, in such Proforma as may be prescribed by Central Adoption Resource Authority in respect of children given to Indians and others for adoption from time to time.

5.7 Surrender of a Child

The surrender document should be executed at the free will of the biological parents/parent with no compulsion, payment or compensation of any kind by the adoption agency. If the biological parent/s state a preference for the religious up-bringing of the child, their wishes should be respected as far as possible. But ultimately the interest of the child should be the sole guiding factor before the child is placed in adoption.

- 5.8 The parent/s should be informed by the agency of his/her/their right to reclaim the child within 60 days from the date of surrender. He/She/They should be made aware that after the period of 60 days the surrender documents will become irrevocable and the child will be considered free for adoption and the RIPA will be free to place the child in adoption or guardianship within or outside India.

- 5.9 The surrender document should be executed on prescribed stamped paper in the presence of two responsible witnesses of whom one should be responsible person who is not an employee of the organisation. The documents shall also be signed by a Notary/Oath Commissioner. The recognized/licensed Indian placement agency should be able to produce these witnesses if necessity arises. The responsibility for ensuring the authenticity of the surrender document would rest on the agency. In case of a minor surrendering a child, the signature of parents/relatives of the minor should be obtained, one of whom should be the person accompanying the minor. The State Govt. may cross check all surrender documents. During the surrender process, the RIPA should ensure that:

- (i) If a child is surrendered, both parents sign the relinquishment document and in case a parent/s is dead, proof of death is furnished. Where a death certificate is not available, a certificate from the Sarpanch/Panchayat/Govt. Authority should be made available.
- (ii) In case of a single mother, only she herself and none else, surrenders the child.
- (iii) Where both biological parents of the child are dead, he or she cannot be surrendered by relatives and will be treated as an abandoned child and the requisite procedure will follow.
- (iv) When a child is born to a married couple but is surrendered by one biological parent and the whereabouts of the other are not known, it will be treated as an abandoned child and the requisite procedures will be followed.
- (v) If the document of surrender is considered invalid/incomplete, the same procedure is followed as for an abandoned child.
- (vi) CARA will reserve the right to refer any Surrender Deed for the State Government's verification.

5.10 Abandoned Child

The procedures for declaring an abandoned child free of adoption will be as per the relevant provisions of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act-2000 and concerned State Rules in this regard.

5.11 Reporting

A monthly statement on status of children, number of Indian adoptions and lists of all registered prospective adoptive parents will be sent to ACA and the concerned department of the State Government. All RIPAs shall send their Annual Reports, audited statement of accounts and a copy of FCRA to CARA which should include statement on adoption fees, donations and data on children adopted during the period.

5.12 Transfer of Children

The procedure of transfer of child will be followed as applicable in JJ Act, 2000 or concerned State JJ Rules in this regard. All transfer cases should be informed to the concerned ACA. All such children transferred to the Recognised Indian Placement Agency (recognised by CARA, GOI) from an unrecognized agency, whether within the State or from outside, should be in the physical custody of the Recognised Indian Placement Agency for a period of not less than one month before any action for the adoption of the child abroad is initiated. This is applicable in case of transfer of children from branches of the same organisation also.

5.13 Transfer of the child should be accompanied by available documents pertaining to its admission, preliminary case history, documentary evidence to prove that the child is legally free for adoption, and a letter of transfer. In addition, the photograph of the child, CSR, PER and other relevant documents should be sent. The Recognised Indian Placement Agency should verify all the facts before accepting the child, as it is legally responsible for its placement.

5.14 In the case of inter-state transfer of children, the following procedures should be followed:

- a) Children from any orphanage/agency can be transferred to another State with the permission of the State Government.
- b) The child should be registered with the nearest ACA and ACA will make all possible efforts to find suitable Indian parents within the stipulated period.
- c) If there is no ACA in the State of origin then ACA registration has to be done in the State to which the child has been transferred.

5.15 Follow-up

RIPA will regularly receive follow up reports from EFAA and inform about any disruption or negative report about any child to CARA. It shall also monitor progress reports of children placed in in-country adoption as per In-country Guidelines.

5.16 Records

The following records and registers should be maintained by every RIPA/ Licensed Indian Placement Agency.

- (i) Master Admission Register as prescribed.
- (ii) A separate file on each child in the prescribed format, giving the full details/history. Relevant legal documents of every adoption and child's background/history should be maintained at least for a period of 18 years, for future reference. The file should have other relevant information i.e. immunization chart, medical history etc.
- (iii) Separate register of prospective Indian, NRI and Foreign adoptive parents with details.
- (iv) Separate follow-up register for children placed both in Domestic and Inter Country adoption.

- (v) Quarterly reports in the prescribed format as forwarded to the State Government, Central Adoption Resource Authority and ACA.
- (vi) The annual report of the organisation clearly reflecting its adoption and other social and child welfare activities.
- (vii) An audited statement of accounts, together with a copy of FCRA account submitted to the Home Ministry.
- (viii) Other records stipulated under the Societies Registration Act, 1860 or the relevant State Law relating to public trusts

5.17 Recovery of Costs in case of Inter-country Adoption

- (a) The organisation will pursue only non-profit objectives. Under no circumstances should it derive improper financial gain from any activity related to inter-country or in-country adoption. In inter-country adoption, an adoption fee of a fixed amount of US\$3500 or its equivalent in Indian rupees will be payable by the adoptive parents to the Recognised Indian Placement Agencies through EFAA or a central authority. This fee will include the cost involved in providing quality child care, medical and legal services, passport, visa, payment towards professional staff, monitoring, correspondence, preparation of child study reports, medical reports, etc. This outer limit of recoverable expenses may be reviewed by CARA/Govt. of India once in a period of five years depending upon escalation of the expenses including cost of living. In case of disruption or failure of adoption, the cost of repatriating the child to India, will be borne by the Enlisted Foreign Adoption Agency, if no alternative placement for the child is effected in the foreigner's country with the concurrence of the Recognised Indian Placement Agency.
- (b) No donation shall be received by a Recognised Indian Placement Agency from a Foreign Prospective Adoptive Parent/Parents or Enlisted Foreign Adoption Agency.
 - (i) If it comes to CARA's notice that any RIPA charges more than the prescribed fees or tries to financially exploit the sponsoring agency/adoptive parents, CARA may after giving an opportunity to such agency to explain its position, suspend or withdraw its recognition as well as recommend criminal prosecution to the State Govt. as per law i.e. in terms of the principles of accountability of the person found defaulter. Similarly, if any Enlisted Foreign Adoption Agency induces a Recognized Adoption Placement Agency by giving offers of more money than the prescribed fees for processing a case of

inter-country adoption of an Indian child, CARA may after giving an opportunity to such agency to explain its point of view, de-enlist the foreign agency along with recommendation to prosecute the defaulters as per law of that country.

- (ii) There should not be any agreement between Indian and Foreign Agencies on number of children to be offered for adoption to foreign families. Similarly, no such agreement on donations and fees will be entered between such Agencies.

5.18 Renewal of Recognition of RIPA

RIPA should apply for renewal of recognition, 6 months prior to the date of expiry of the previous recognition. The original application should be sent by the agency to the appropriate authority of the State Government and a copy of it should simultaneously be forwarded directly to CARA. The State Government will forward the original application to CARA along with its comments within a period of two months from the date of receipt of the complete application. If the State Government does not respond within three months from the date of receipt of application, CARA may conduct a joint inspection and consider the renewal of recognition. Recognition would normally be renewable for a period of three years subject to the following conditions:

- (a) Recommendation/views of the concerned State Government accompanied by the inspection report of the Agency.
- (b) Satisfactory performance in relation to in-country adoption will be an important factor to assess and consider further renewal of recognition of any RIPA. The agencies shall sufficiently exhibit their involvement in the area of In-country adoption. The Agencies will place 50% or more children in adoption to Indians in India.
- (c) Regular submission of Annual report, quarterly reports of the Agencies and audited statement of accounts as prescribed, adoption charges per child, donations received, if any.
- (d) No instance of proved malpractice against the RIPA.
- (e) Whether the agency is still recognized by the appropriate authority of concerned State govt. for running the children Home and doing in country adoption under relevant rules.
- (f) List of children placed in in-country and inter-country adoption, year-wise for the period of three years to support the data submitted.

5.19 Agencies to maintain Accounts

- i) Every agency shall maintain proper accounts to be audited by a Chartered Accountant every year.
- ii) An attested copy of audited accounts together with audit report shall be furnished by every agency within one month from the date accounts have been audited by the Chartered Accountant, to the relevant Department of the State Government concerned and to the CARA.
- iii) An attested copy of the FCRA accounts submitted to the Home Ministry should be furnished to CARA together with the audited accounts, by the agency. The adoption charges and donations received from different sources will be submitted to CARA at the end of every financial year.

5.20 Recognised Indian Placement Agencies to deal with Enlisted Foreign Adoption Agencies only

No Recognised Indian Placement Agency shall entertain any application for adoption of an Indian child from foreigners [including NRIs/PIOs (as applicable)] unless it is forwarded through Enlisted Foreign Adoption Agency/central authority or from the appropriate Government authority/duly authorized body in countries where there is no enlisted agency. The Recognised Indian Placement Agency should not entertain an application direct from any foreign individual or Foreign Agency that is not enlisted by CARA.

5.21 Inspection of Agencies

The premises of the Recognised Indian Placement Agencies including their children Homes, and their records shall be open to inspection by CARA, State Government or any other agency authorized by CARA.

5.22 De-recognition

Recognition can be withdrawn or suspended by CARA wherever the need arises after giving due opportunity to the agency by way of show cause notice. No recognition is granted on a permanent basis and the same shall be subject to review from time to time.

5.23 Safeguards

- (i) No contact between the FPAPs and the biological parents will be allowed. Counseling facilities should be made available to biological mother/parents by the adoption agency. Consent of the biological mother cannot be obtained before the birth of the child.
- (ii) No child should be proposed for intercountry adoption before ACA Clearance except in the case of NRIs

- (iii) RIPA will maintain the confidentiality of the child's origin, his or her parents
- (iv) No one shall derive improper financial gain or other gain from an activity related to adoption. A receipt shall be issued in case of receipt of any payment for any service rendered.
- (v) There can't be any direct adoption by any FPAPs and all such adoptions shall be through recognized/enlisted agencies as defined under the Guidelines
- (vi) All RIPAs shall adhere to strict ethical practices and work in the best interest of children as defined in the Guidelines and described in Hague Convention on Inter-country Adoption-1993 failing which action as deems fit will be taken against any defaulting agency/ies. The office bearers of the agency/ies will be held responsible for any breach of procedural safeguards or non-compliance of ethical practices.

CHAPTER-VI

ENLISTED FOREIGN AGENCIES FOR ADOPTION (EFAA)

6.1 Foreign Agencies to Apply to India's Diplomatic Missions

A foreign social/child welfare agency desirous of sponsoring applications of foreign adoptive parents for adopting an Indian child shall make an application for authorization to CARA through the Office of Indian Diplomatic Mission in that country and only such foreign agencies enlisted for this purpose by CARA shall undertake this activity.

6.2 Criteria for Enlistment of Foreign Agencies

The criteria for enlistment/authorization of foreign agencies by CARA for the purpose of inter-country adoption are as under:-

- (i) It will be an Agency duly registered under the relevant law of the concerned country and should be recognized/ licensed by the appropriate authority of that country to undertake inter-country adoption.
- (ii) It must have been duly accredited and authorized by the Competent Authority under the Hague Convention on Inter-country Adoptions, 1993 (wherever applicable).
- (iii) It will submit the Memorandum, Mission statement, copies of Registration status, latest license issued by the concerned Government authority to undertake domestic and International Adoptions, list of Board/Executive Members and list of countries it is working with.

- (iv) It shall be a child welfare agency with an established standing in this field and it must be staffed with qualified social workers who have experience in the field of adoption. It shall submit the activities of the organization, Annual Reports for the last 3 years, list of staff with qualification and accounts for the last two years.
- (v) The agency shall run on a non-commercial and non-profit basis and shall provide an annual statement on payment made to the Indian agencies.
- (vi) An undertaking by the enlisted foreign adoption agency that in case of disruption of the foreigner's family before adoption is effected or in case the child is not properly looked after or is mistreated or abused in the adoptive family, it will undertake responsibility for the care of the child under intimation to the Indian Diplomatic Mission, the Central Adoption Resource Authority, the concerned Recognised Indian Placement Agency immediately with full details and action taken for care and protection of the child. This shall include finding a suitable alternative placement for the child with the concurrence of the Recognised Indian Placement Agency, which processed the case and report such alternative placement to the Indian Court, which made the order for Guardianship. In such a case wherein the child is being repatriated to India either to his/her biological family, or to the Recognised Indian Placement Agency or to any other organisation, CARA should be consulted. All Social and Medical Reports should be furnished. The legal status of the child, his/her rights of citizens in the foreign country and the adoptive parents legal liabilities should be stated. A care plan for the child will be worked out and the State Government or any other organisation authorized by CARA will monitor the well being of the child. All cost including repatriation and after care will be met by the Enlisted Foreign Adoption Agency.
- (vii) The Head/Chief Executive of the Organisation should be willing to sign a written undertaking to follow the Guidelines, to send progress reports as required, to send a copy of the adoption decree.
- (viii) Concerned Departments of the Foreign Govt./Central Authorities which agree to give the aforementioned undertaking will be treated as enlisted Agencies for the purpose of sponsoring the applications of foreign nationals. Central Authorities need not to apply for enlistment with CARA.

6.3 Procedure for Enlistment

- (i) A foreign social/child welfare agency desirous of sponsoring applications of foreign adoptive parents for adopting Indian children

shall apply for enlistment to CARA, through the office of India's Diplomatic Mission and the Government of the country where it is located.

- (ii) On the recommendation of India's Diplomatic Mission in the country concerned, CARA shall examine the application for enlistment and consider the agency concerned for enlistment provided it fulfils the criteria stated in paragraph 6.2 above
- (iii) A foreign adoption agency may be enlisted for a period of 3 years.

6.4 Renewal of Enlistment

- (i) The enlistment would be renewable for 3 years subject to satisfactory performance and fulfillment of terms and conditions attached to its enlistment.
- (ii) Every EFAA should apply for renewal of enlistment to CARA through the concerned Indian Diplomatic Mission, 6 months prior to the date of expiry of the previous recognition.

6.5 De-enlistment

The Central Adoption Resource Authority, Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India, may at any time de-enlist any Enlisted Foreign Adoption Agency for adoption for valid or legitimate reasons to be recorded in writing. However, if at the time of de-enlistment there is any case under process that would be allowed to be completed unless CARA decides it will not be in the best interests of the child to do so. Non-submission of regular progress reports can lead to de-enlistment.

6.6 Follow-up Report

- (a) The EFAA/Central Authority with reference to every child, shall send, follow-up reports with photographs of the child on a six monthly basis for a period of 2 years or until such time as the legal adoption is completed and citizenship is acquired in the receiving country to
 - i) CARA
 - ii) Court that awarded the guardianship in India
- (b) The EFAA/central authority will forward a copy of the legal adoption order of the appropriate Authority in that country as soon as it is made to:
 - 1. CARA
 - 2. The Court that awarded the guardianship in India
- (c) Where the child is not legally adopted by the adoptive parents in the receiving State within two years from the date of order of the Court in India appointing the adoptive parents as guardians either on

account of disruption in the family or on account of the adoptive parents failing to get adjusted to the behaviour of the child or otherwise, the foreign EFAA which has processed the adoption of the child in the receiving State should immediately withdraw the child from the adoptive parents and keep the child in its custody and care and find out new adoptive parents for placement of the child in adoption as soon as possible. The foreign agency shall give an undertaking to this effect to the Court processing the case in India.

- 6.7 EFAA or Central Authority in the receiving country may arrange get-together of children of Indian origin and their adoptive families from time to time and may also involve concerned Indian Diplomatic Missions.

CHAPTER-VII

ROLE OF INDIAN DIPLOMATIC MISSIONS ABROAD

- 7.1 The Indian Missions located in different countries will play a significant role in the process of Inter-country adoption of Indian children. The Missions will help CARA in maintaining liaison with the different authorities and agencies operating in the countries of their jurisdiction. The role envisaged for the Missions broadly fall under the following categories:-
- i) The recommendation for fresh enlistment and subsequent renewals of foreign agencies desirous of working with India.
 - ii) Attestation of Dossier/documents of prospective adoptive parents submitted by the foreign authorities/agencies before the same is sent to CARA, (wherever the 1961 Hague Convention on Abolishing Requirement of Legalization for Foreign Public Documents is not applicable).
- 7.2 While recommendations for fresh enlistment should be made by the concerned Indian Embassy/High Commission only, in case of renewals, the same may be recommended by the Offices of the Consulate Generals and Dy. High Commissions also.
- 7.3 In case of Indian passport holders residing in a country where there is no enlisted agency or where they cannot be recommended by the host Govt. as per local laws, the Indian Embassy may authorise a qualified social worker to do the Home Study Report (HSR) and other documentation including Undertaking to send progress reports etc. and send the dossier to CARA with its recommendation.

- 7.4 Whenever a report is received on adoption disruption of an Indian child by a foreign couple, the Embassy should contact the local central authority and other concerned authorities to ensure that the interest of the child is being looked after. A report in this regard should also be sent to CARA at the earliest.
In case the child is required to be returned to India, the Embassy may render necessary help and facilitate the repatriation of the child in consultation with the local authorities, agency and CARA.
- 7.5 The Embassy should communicate any report or observation which it feels is important and relevant vis-à-vis inter-country adoptions to CARA.
- 7.6 At the time of attestation of documents, the Embassy should ensure the inclusion of duly authenticated English translation if the documents are in a language other than English.

CHAPTER-VIII

ADOPTION COORDINATING AGENCY (ACA)

- 8.1 There will be an Adoption Coordinating Agency (ACA) in a State or in special circumstances for a group of states where there are several children homes and adoption agencies to carry out the functions prescribed under the Guidelines and as assigned to it by CARA from time to time.
- 8.2 The ACA shall be registered under the Societies Registration Act, 1860 or authority created by the State Government with detailed Rules and Regulations and will comply with all the Rules laid down under the Act and also Guidelines.
- 8.3 **Functions:**
- i) The ACA will receive periodically a list of children who are legally free for adoption every month from the following and shall maintain a register for the same:
 - (a) Recognized Indian Placement Agencies.
 - (b) Licensed Adoption Placement Agencies.
 - (c) Government Homes.
 - (d) Other children's Homes.
 - ii) It will coordinate the work of all its Member Agencies and other Child Welfare Institutions in the field of Indian adoption.
 - iii) It shall call for a periodic meeting of Members as per the Memorandum and at least one meeting in each quarter.

- iv) It shall receive details of children who are being sought to be made free for inter-country adoptions from RIPAs and ensure that the priority laid down by the Hon'ble Supreme Court on adoption within the country is adhered to.
- v) It shall register prospective Indian adoptive parents and prepare the HSR of prospective Indian parents where necessary.
- vi) It shall also receive an updated list of prospective adoptive parents from Member Agencies.
- vii) If at the end of 30th day, no suitable adoptive parents are found, the ACA will give a Clearance Certificate to the child placed under their assistance after seeing the child verifying all relevant documents to be placed with foreign adoptive parents. The Clearance Certificate must include a current photo of the child.
- viii) In cases where CARA Guidelines are not being followed by any recognised/licensed agency, the concerned ACA will bring it to the notice of State Government and CARA.
- ix) The ACA should undertake programmes for promotion of in-country adoption.
- x) It should undertake Training Programmes to upgrade the skills of adoption functionaries.
- xi) It should provide pre and post adoption counseling wherever required.
- xii) The ACA shall promote observance of quality childcare, health and hygiene at placement agency. Any irregularities or neglect of children should be reported to CARA.
- xiii) All ACAs shall submit to CARA an annual report including an audited statement of accounts and activities conducted throughout the year.
- xiv) It will feed regular information on children placed under ACA assistance to CARA for preparing a Central Pool.
- xv) The ACA will carry out any other tasks in the field of adoption as directed by CARA from time to time.
- xvi) The ACA will make all possible efforts to place a child in in-country adoption through inter-VCA coordination before issue of clearance to the child for placement in inter-country adoption within the prescribed period.

8.4 ACA shall have a minimum of two professionally trained persons

8.5 Recognition

Every recognised ACA should apply for renewal of recognition, 6 months prior to the date of expiry of the previous recognition.

- a) The recognition will be normally for period of three years. CARA may accord recognition for less than 3 years depending on the performance of the particular ACA.

(b) Criteria for Recognition

In order to be recognised as ACA, an agency must fulfill the following criteria:-

- i) It should be a society registered under the Societies Registration Act, 1860 or an authority created by concerned State Government with detailed Rules & Regulations.
- ii) The agency must be recommended by the concerned State Government for recognition by CARA.
- iii) The agency should run on a non-commercial and non-profitable basis.
- iv) Undertaking to Comply with CARA Guidelines.
- v) All the Office-bearers should be Indian Nationals.

(c) Renewal of Recognition

ACA which seeks renewal of recognition should apply to CARA through the State Government for renewal of recognition six months prior to the date of expiry of the previous recognition. If the State Government does not respond within the stipulated 60 day period from the date of receipt of application, it shall be presumed that the State Government has no objection. However, CARA may issue recognition after Joint Inspection of CARA and State Government. The following would be the main criteria for renewal of recognition

- i) Satisfactory performance in the promotion of in-country adoptions.
- ii) Timely submission of reports and audited statement of accounts as may be specified by CARA,
- iii) Compliance with Guidelines.

(d) Withdrawal of Recognition

Recognition of ACA may be withdrawn by CARA for violation of Terms & Conditions as given in these Guidelines after giving the ACA an opportunity to explain its position. Any malpractice, if proved, would immediately invite action in the shape of withdrawal of recognition. Delay and non-compliance in the submission of reports/accounts asked for by the State Government or CARA may also be a ground for withdrawal of recognition.

In the event of withdrawal of recognition CARA shall evolve suitable alternate mechanism for issue of Clearance Certificates.

8.6 Membership of ACA

All the Recognised Indian Placement Agencies, Licensed Adoption Agencies, Sishu Grehs and Government run Children Homes would be required to become members of an ACA. Child welfare agencies, which are not placing children in adoption but are running Homes for children etc. would also be eligible to be members of the ACA. Any agency de-recognised by CARA or de-licensed by the State Government shall cease to be a member of an ACA and it shall not be eligible for membership of an ACA unless it is once again recognised or licensed. Adoptive Parent Associations shall also be eligible for membership. Individuals with expertise in adoption/child welfare may be enrolled as members. The above will constitute the General Body of the ACA.

8.7 Structure of ACA

There shall be an Executive Committee for managing the affairs of an ACA. The Executive Committee shall consist of not less than 5 members. Only ACAs recognised by CARA can carry out the functions envisaged in these Committees. Where there is no ACA existing, reputed Child Welfare organisation or an academic body can function as ACA in accordance with existing Guidelines for ACA formation. CARA, in consultation with State Government, may identify such an organisation not involved in adoption placement work. However, its recognition as an ACA shall come through the State Government if all other conditions are met.

The office bearers of the Executive Committee of an ACA will consist of a Chairperson, Secretary and Treasurer. Who shall be elected from and by the General Body of Members of the ACA for a term of 3 years. No office bearer shall be from any inter-country adoption agency. Office bearer shall not hold office for more than two consecutive terms.

The tenure of Executive Members will be for a period of 3 years.

The Executive Committee shall consist of the following Members:

1. Chairperson, Secretary, Treasurer;
2. One representative of the State Government not below the rank of Assistant Director;

3. One representative of the Scrutiny Agency/Agencies working in the jurisdiction of the concerned ACA;
4. One representative of the agencies exclusively involved in Indian adoption (without having Inter-country Adoption recognition);
5. One representative of the Recognised Indian Placement Agencies (Inter-Country) wherever existing;
6. One representative from Adoptive Parents Associations, wherever existing;
7. One representative from the Deptt. of Health, State Govt.
8. One representative from the Academic Community preferably from the field of Social Work/Law/Child Development without any direct link with the adoption agencies.

The representation from Points 2 to 7 shall be on a rotation basis wherever there are more such agencies/organizations. Representative of the Scrutiny Agency in the ACA Executive Committee should not be member of the Adoption Scrutiny Committee.

- 8.8 The Executive Committee of an ACA may appoint staff to carry out the day-to-day functions of the ACA. Such paid staff would be accountable to the Executive Committee.
- 8.9 No Recognized Indian Placement Agency shall process the application of foreign families for inter-country adoption before obtaining the Clearance Certificate (CC) from the ACA.
- 8.10 **ACA Clearance Certificate**
The ACA clearance certificate shall have two signatures. This comprises the Chairperson and Secretary of the ACA. The procedure will be followed as per Para 4.1 Step II of the Guidelines.
- 8.11 **Existing VCAs**
The existing VCAs shall be reconstituted within a period of six months of issue of these Guidelines and will be known as ACA.

No organisation can function as an ACA as prescribed in the Guidelines without a valid recognition of CARA.

CHAPTER-IX

CENTRAL AUTHORITIES

- 9.1 By virtue of ratification of Hague Convention, all RIPAs will be treated as accredited agencies of CARA. The Application of PFAPs shall be transmitted to the Central Authority of the State of origin by the Central Authority of the Receiving country directly or through one of its Accredited Bodies with its approval.

The Central Authorities of the receiving countries have to declare in their letter of approval that:

- the PFAPs/NRIs are eligible & suitable to adopt a child from India as per the Law of their countries.
 - the Home Study Report & Health Report (by the medical professional) of the PFAPs are prepared by the professionally trained social workers of the agencies/bodies accredited by the authority.
 - the PFAPs have agreed to the proposed adoption.
 - the child will be authorized to enter & reside permanently & will be treated at par with other natural born citizen of the country.
- 9.2 With reference to every child, it shall send either directly or through its accredited agencies follow-up reports with photographs of the child on a six monthly basis until such time till legal adoption is completed and the child becomes the citizen of the receiving country to:
- 1) CARA
 - 2) Court that awarded the guardianship in India
- 9.3 In case of any disruption etc. it shall take appropriate measures as envisaged under Art. 21 of the Convention, including, inter alia:
- to inform CARA immediately the disruption & the possibility of child's placement with a new prospective adoptive parent;
 - and where this is not appropriate or possible, to arrange long term care under intimation to CARA;
 - it shall arrange for the return of the child to India if his/her interest so required due to the disruption.

S90 GI/06-12

CHAPTER-X

MISCELLANEOUS

10.1 Violation of Guidelines

If it comes to the notice of any State Government or any of India's Diplomatic Missions abroad or CARA or any other source that a RIPA or EFPA is not observing all or any of the provisions of these guidelines or is otherwise functioning in a manner which is not in the interest of children CARA may, at its discretion suspend or withdraw recognition of such enlisted agency or placement agency and/or take any other such action as may be deemed necessary.

10.2 Apprehensions have been expressed that unscrupulous elements arrange illegal transfer of babies to adoptive parents at the time of their birth in some hospitals, nursing homes, maternity homes in the country. Such transfer of babies taking place without observing the appropriate norms and procedure is illegal and thus it is not at all in the interest of the child. If any such complaints are brought to the notice of CARA, it shall advise the State Government to cause an enquiry to be made and take up the matter with the appropriate authorities of the Central or State Government including the Medical Council of India.

10.3 Cases deserving relaxations

In the light of obligations as a result of ratification of the Hague Convention on Inter-country Adoption-1993 and in the best interest of Indian children, CARA and the Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India shall take all appropriate measures from time to time. In all cases of clearances for inter-country adoptions, recognitions, enlistments and renewals of all concerned agencies, decisions will be taken at the discretion of CARA and in such cases where CARA feels that a particular provision needs to be relaxed, it may do so by recording on file the reasons as to how the best interest of the child is being served by such relaxation.

10.4 Amendments to Guidelines

The Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, reserves to itself the power, at its discretion to make such amendments, additions, deletions or alterations in these guidelines as are deemed necessary from time to time.

GLOSSARY OF TERMS

Adoption Coordinating Agency (ACA):

ACA is an agency in a state/region set up for the promotion of In-country Adoption through co-ordination of its member agencies, and recognized by CARA and to issue clearance certificate for a child to be placed in inter-country adoption.

Adoption Scrutinising Agency (ASA):

An independent Social/Child Welfare Agency appointed by the Court for scrutinizing adoption applications for In-country and Inter-country Adoptions.

Central Adoption Resource Authority (CARA):

An autonomous body functioning under Ministry of Social Justice & Empowerment to act as a Central Authority in the matter of adoptions.

Central Authority (CA):

As defined under Hague Convention on Inter-country Adoption-1993.

Child Study Report (CSR):

It will contain details about the child, its date of birth, social background etc.

Child Welfare Committee (CWC):

A Committee as defined in JJ Act-2000 to deal with children in need of care & protection.

Clearance Certificate (CC):

A certificate issued by ACA permitting the RIPA to place a child in Inter-country Adoption. Clearance Certificate is required in case of all adoptions placed with foreigners and PIO.

Enlisted Foreign Adoption Agency (EFAA):

A Foreign Social/Child Welfare Agency that is enlisted by CARA for sponsoring the application of Prospective Foreign Adoptive Parents/NRI for Inter-Country Adoption of an Indian child.

FPAP:

Foreign Prospective Adoptive Parents.

G.A.W.A.:

Guardian and Wards Act, 1890

H.A.M.A:

Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956

Home Study Report (HSR):

It contains details of the adoptive family/Couple's Social Status & family background; Description of Home; Standard of Living; Relationship; Health details; Economic Status etc.

In-Country Adoption (IA):

Adoption of an Indian child by Indian parents residing in India.

Inter-country Adoption (ICA):

Legal placement of an Indian child with a prospective NRI, PIO parents and foreign nationals.

JJ Act-2000:

Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act-2000

Licensed Adoption Placement Agency for In-Country Adoption (LAPA):

An Indian Social/Child Welfare Agency licensed/recognized by the State Government for In-country Adoption.

No Objection Certificate (NOC):

A Certificate issued by CARA permitting the child to be placed with a prospective adoptive parents for Inter-country adoption.

NRI:

Non-Resident Indian/Indians (holding Indian Passport).

Physical Examination Report (PER):

It will contain medical report of the child, report of hospitalization if any etc.

PIO:

Persons of Indian Origin.

Recognized Indian Placement Agency for Inter-country Adoption (RIPA):

An Indian Social/ Child Welfare Agency recognized by CARA for placement of Indian Children in Inter Country Adoption.

ANNEXURE-1**Central Adoption Resource Authority (CARA)**

The functions of the CARA will be as follows:

1. To act as the Central Authority with regard to Adoption matters as envisaged under the Hague Convention on Protection of Children and Cooperation in respect of Inter country Adoption, 1993.
2. To coordinate with the State Governments for promoting in-country adoption and all other related adoption matters including regulation and monitoring of RIPAs and ACAs.
3. To recognize/renew the Indian Placement Agencies as accredited bodies for processing inter-country adoption cases.
4. To enlist/renew enlistment of foreign adoption agencies as authorized bodies to sponsor applications for Inter country Adoption of Indian children.
5. To recognize/renew an Adoption Coordinating Agency (ACA) to promote Indian adoption.
6. To receive applications or copies of applications along with requisite documents (as prescribed by the Supreme Court of India in CRL (WP) No. 1171/1982 in the matter of Shri Laxmi Kant Pandey Vs. Union of India and Others) of foreigners desirous of taking Indian children in adoption through a recognized social or child welfare agency in the foreign country or through an organization owned or operated by the Government in that country.
7. Whenever such applications are received directly by Central Adoption Resource Authority to forward such applications to one of the Indian social or child welfare agencies recognized by CARA for processing applications of foreign parents for adoption in the competent court.
8. To issue "No Objection Certificates" in inter-country adoption cases.
9. To receive particulars of children placed under ACA assistance from all the ACAs for the purpose of establishing a Central Information Pool on such children. At the same time, information relating to the number of prospective adoptive parents registered with ACAs will also be obtained.
10. To receive periodical data in the prescribed format from Recognised Indian Placement Agencies (RIPAs) regarding children in their care and children placed in adoption, both in-country and Inter-country. At the same time, information relating to the number of prospective adoptive parents registered with them will also be obtained.
11. To inspect and evaluate the working of RIPAs and ACAs through State Governments or any other agency or body constituted for the purpose.
12. To call for annual audited statements of account from Recognised Indian Placement Agencies (RIPAs) and Adoption Coordinating Agencies (ACAs).

13. To call for annual statements from Enlisted Foreign Adoption Agencies on Indian children placed by them in the prescribed format.
14. To send yearly data to Indian Diplomatic Missions abroad in respect of Indian children taken abroad.
15. To receive periodical reports about the progress of the children taken abroad by parents for the purpose of adoption in a Proforma prescribed by CARA from all Enlisted Foreign Adoption Agencies (EFAAs) in foreign countries through India's Diplomatic Mission in the country where such agencies are located and to examine such reports and to take such follow-up action as deemed necessary.
16. To arrange training programmes for functionaries of adoption Agencies, Govt. Homes/Shishu Grehas and other professionals and bring about standardization of training courses.
17. To initiate action on any other activity relating to adoption as a child's right to a family.
18. To enter into bilateral agreement with Foreign Central Authorities wherever necessary as prescribed under the Hague Convention.
19. To liaise with concerned Central Authority/other appropriate Authority, Enlisted Agency and RIPA in case of disruption of a child placed in inter-country adoption and to take action in the best interest of the child.
20. To take suitable action against any recognised/enlisted agency on notice of any unethical practice in inter-country adoption or on violation of the present Guidelines and further, to request the competent authority to cause an inquiry/investigation and to take appropriate action against such defaulting person/Agencies.

ANNEXURE-2

LIST OF DOCUMENTS REQUIRED FROM EFAA

List of documents required from foreign adoptive parents and Social or Child Welfare Agency enlisted by Government of India for consideration of an inter-country application of Indian Child

- (a) Home Study Report* of the foreign adoptive parents prepared by a professional social worker of EFAA/person authorized by Central Authority/Government Departments.
- (b) Recent photographs of the adoptive parents/family.
- (c) Marriage certificate of prospective adoptive parents.

- (d) Certificate of medical fitness of adoptive parents duly certified by a medical doctor.
- (e) Declaration regarding financial status of prospective adoptive parents along with supporting documents, employer's certificate/Income Tax Return Order and Bank references.
- (f) Three reference letters from acquaintance/relatives regarding suitability of PAPs to adopt.
- (g) Adoption decree of previously adopted child/children, if any.
- (h) Police clearance report.
- (i) Birth certificate/passport, as proof of age
- (j) Approval of the Central Authority (suitability report - HSR).
- (k) Documentary proof of citizenship/nationality of PAPs.

*Home study report should include (a) Social status and family background; (b) Description of Home; (c) Standard of living as it appears in the Home; (d) Current relationship between husband and wife; (e) Current relationship between the parents and children (if any children); (f) Development of already adopted children (if any); (g) Current relationship between the couple and the members of each other's family; (h) Employment status of the couple; (i) Health details such as clinical test, hear condition, past illness, etc. (medical certificate, etc.); (j) Economic status of the couple; (k) Accommodation for the child; (l) Schooling facilities; (m) Amenities in the Home; (n) Reasons for wanting to adopt an Indian child; (o) Attitude of grand-parent and relatives towards adoption; (p) Anticipated plans for the adoptive child; and (q) Legal status of the prospective adoptive parents.

- (l) Undertaking from EFAA sponsoring the foreigner to the effect that child would be legally adopted by the foreign adoptive parents according to the law of the country within a period not exceeding two years from the time of arrival of the child and as soon as the adoption is effected, the enlisted agency will send certified copies of adoption order each to all concerned.
- (m) Undertaking from the EFAA that follow up report relating to progress of the child along with his/her recent photograph would be sent six monthly basis for a period of 2 years or until such time as the legal adoption is completed and citizenship is acquired in the receiving country.
- (n) Power of Attorney from prospective adoptive parents in favour of office/official of RIPA in India which will be required to process the case and such Power of Attorney should authorise the Attorney to handle the cases on behalf of the foreigner in case the foreigner is not in a position to come to India.

- (a) Undertaking from the EFAA to the effect that in case of disruption of the family of the foreigner before legal adoption has been effected, it will take care of the child and find a suitable alternative placement for the child with the approval of Central Adoption Resource Authority. After seeking the necessary approval from CARA, it will report alternative placement to the concerned Indian court handling guardianship proceedings with the help of concerned RIPA and such information shall be passed on to all concerned as per Para 6.7(b).
- (p) Undertaking from the EFAA that it will pay adoption fee to the concerned RIPA as per para 5.17 of the Guidelines.
- (q) Certificate from EFAA sponsoring application of the foreigner to the effect that adoptive parents are permitted to adopt a child according to the law of their country and the child will receive an entry permit/visa.

ANNEXURE-3

LIST OF DOCUMENTS
TO BE SUBMITTED BY RIPA TO CARA FOR OBTAINING NOC

- (a) RIPA should apply on the format prescribed by CARA
- (b) All documents listed under Annexure-2
- (c) "Child Study Report" duly accepted and approved by PAPs (notarized/attested as per Para 4.1 Step I)
- (d) Physical Examination Report of the child duly accepted and approved by PAPs (notarized/attested as per Para 4.1 Step I)
- (e) Proof of the child legally free for adoption (CWC certificate/copy of the surrender deed).
- (f) ACA clearance certificate (not required for NRI).

ANNEXURE-4

TENTATIVE TIME SCHEDULE
FOR PLACEMENT OF CHILDREN IN INTER-COUNTRY ADOPTION

Sl. No.	Services to be rendered by concerned Agency/Authority	Proposed Time frame
1.	RIPA to place a child in domestic adoption	Within 30 days from the date on which the child is legally free for adoption.
2.	ACA to issue a Clearance Certificate	On 31 st day in case of a normal child and within 10 days in case of a special needs child.
3.	CARA to issue NOC for inter-country adoption.	Within 15 days from the date of receipt of NOC application from RIPA, complete in all respect.
4.	RIPA to file the case in the competent Court for an appropriate order after CARA NOC	Within 15 days from the date of receipt of NOC from CARA.
5.	The competent Court to dispose the case	Within 02 months from the date of filing of application by RIPA, complete in all respect.
6.	The concerned Passport Office to issue passport for the child	Within 10 days from the date of submission.